सूर्योदय 5:38 सूर्यास्त 7:17

आज का तापमान

शिमला	17.4 न्यू	21.4 अधि
धर्मशाला	17.6 न्यू	28.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	78,094
निफ्टी	24,383

सोना 1,42,000 चांदी 2,17,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 17 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 98, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

दिल्ली दंगा : ताहिर समेत 5 को उम्रकैद

आईबी अफसर की हत्या के दोषी; कोर्ट बोला- घटना गंभीर, इसने समाज को झकझोर दिया

एजेंसी, नई दिल्ली। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वारदात थी, जिसने समाज को झकझोर दिया। कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण,

दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था। वहीं, 11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था, 'आरोपियों ने सारी हदें पार कर दीं। अंकित की मौत होने के बाद भी उन पर हमला जारी रखा गया।

यह बेहद क्रूर और सुनियोजित हत्या थी। इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। ताहिर हुसैन के वकील ने दलील दी थी कि हर हत्या के मामले में मौत की सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी दोषी की अलग-अलग भूमिका साफ नहीं बताई गई। इसलिए यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं आता।

- **ताहिर के वकील ने कहा- रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं**
- **पुलिस ने मौत की सजा मांगी थी**

हिंसाग्रस्त इलाके के नाले में मिला था अंकित का शव

दिल्ली दंगा 23 फरवरी, 2020 से शुरू हुआ था। 25 फरवरी को आईबी अफसर अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आए। परिवार उनकी तलाश कर रहा था, तभी लोगों ने बताया कि उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले में देखा गया है। अगले दिन सुबह पुलिस ने नाले से अंकित का शव बरामद किया था। इसके बाद पिता रविंदर कुमार की शिकायत दयालपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। उनका आरोप था कि अंकित की हत्या तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने की है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ताहिर हुसैन के ऑफिस में इकट्ठा हुए थे और हत्या के बाद अंकित के शव को नाले में फेंक दिया गया।

सीएम शुभेंदु की रेकी कर रहा जैश का आतंकी काबू

एजेंसी, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने पूर्वी बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने हामिम मंडल नाम के इस शख्स को वीरवार देर रात एक हाउसिंग कांप्लैक्स से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मंडल के मोबाइल और घर से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। पुलिस यह भी कह रही है कि हामिम पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड सज्जाद भट का करीबी है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे।

हिमाचल में उद्योगों को 25 साल तक मिलेगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र : मुख्यमंत्री सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाले सहमति प्रमाण पत्र (कंसेंट सर्टिफिकेट) की व्यवस्था में बदलाव किया है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि अब उद्योगों को एक बार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता उद्योग की श्रेणी के अनुसार पांच से 25 वर्ष तक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 12,500 उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत हैं। नई व्यवस्था लागू होने से उद्यमियों को बार-बार प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी और कारोबार करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है और समय पर कार्य पूरा न होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से बोर्ड का करीब 70 प्रतिशत लिपिकीय कार्य कम होगा और उद्योगों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।

ईरान पर हमले रोकने का बिल एक वोट से गिरा

एजेंसी, वॉशिंगटन। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया। वीरवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े।

ट्रंप की पार्टी के एक सांसद डेव मैककॉर्मिक वोटिंग में शामिल नहीं हुए, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता। यानी राष्ट्रपति खुद यह फैसला नहीं ले सकते थे। ईरान जंग को लेकर विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी सैन्य अभियान पर अंतिम फैसला संसद ही ले। ताजा घटनाक्रम के बाद इसे सीनेट में लाने के लिए दोबारा कोशिश करनी होगी। सैन्य कार्रवाई रोकने का विधेयक फिलहाल अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों से जुड़ी कमेटी के पास है।

स्पेन में घुसने पहुंचे 60 हजार प्रवासी 34 की मौत

एजेंसी, सिउटा। स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान 34 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, घटना तब हुई, जब वीरवार सुबह 3 हजार प्रवासी एकसाथ स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों के कारण लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने व समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हो गए। स्पेनिश सरकार की तरफ से जानकारी मिली है कि 24 घंटे में मोरक्को की तरफ से करीब 60 हजार लोगों के तैरकर या पैदल चलकर स्पेनिश शहर स्यूटा में प्रवेश कर चुके है। यह स्टूटा की आबादी का 70% है।

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाया जाए : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी बच्चों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक आयोजित हुई।

बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 3025.49 करोड़ रुपए के बजट सहित किसान कल्याण, कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मंडियों के आधुनिकीकरण और पुनरोद्धार पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मंडियों में पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही मंडी स्थलों पर पीपीपी मॉडल के माध्यम से कृषि उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने और नियमों को निवेश अनुकूल बनाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने, प्राकृतिक खेती मिशन से किसानों को जोड़ने और प्रत्येक जिले में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रमाणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2025-26 के संशोधित आय-व्यय अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी गई। नए वित्तीय वर्ष के लिए 2228.59 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों और 3025.49 करोड़ रुपए के व्यय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई।

संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे राहुल ने दिया चंदा

एजेंसी, नई दिल्ली। विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दानपेटी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दानपेटी में चंदा डाला। साथ ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर पहुंचे जिसमें 'अमित शाह संसद से गायब क्यों' लिखा हुआ था। इधर, लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 ध्वनि मत से पास हुआ। लोकसभा और राज्यसभा तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। वहीं, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 पारित करने का प्रस्ताव रखा। बिल ध्वनि मत से पास हुआ।

मुख्यमंत्री रेखा ने छात्राओं को वितरित कीं निशुल्क साइकिलें

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में 'विद्या वाहिनी' योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 3,000 से अधिक छात्राओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की गईं।

कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और सपनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 1.40 लाख छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी जाएंगी।

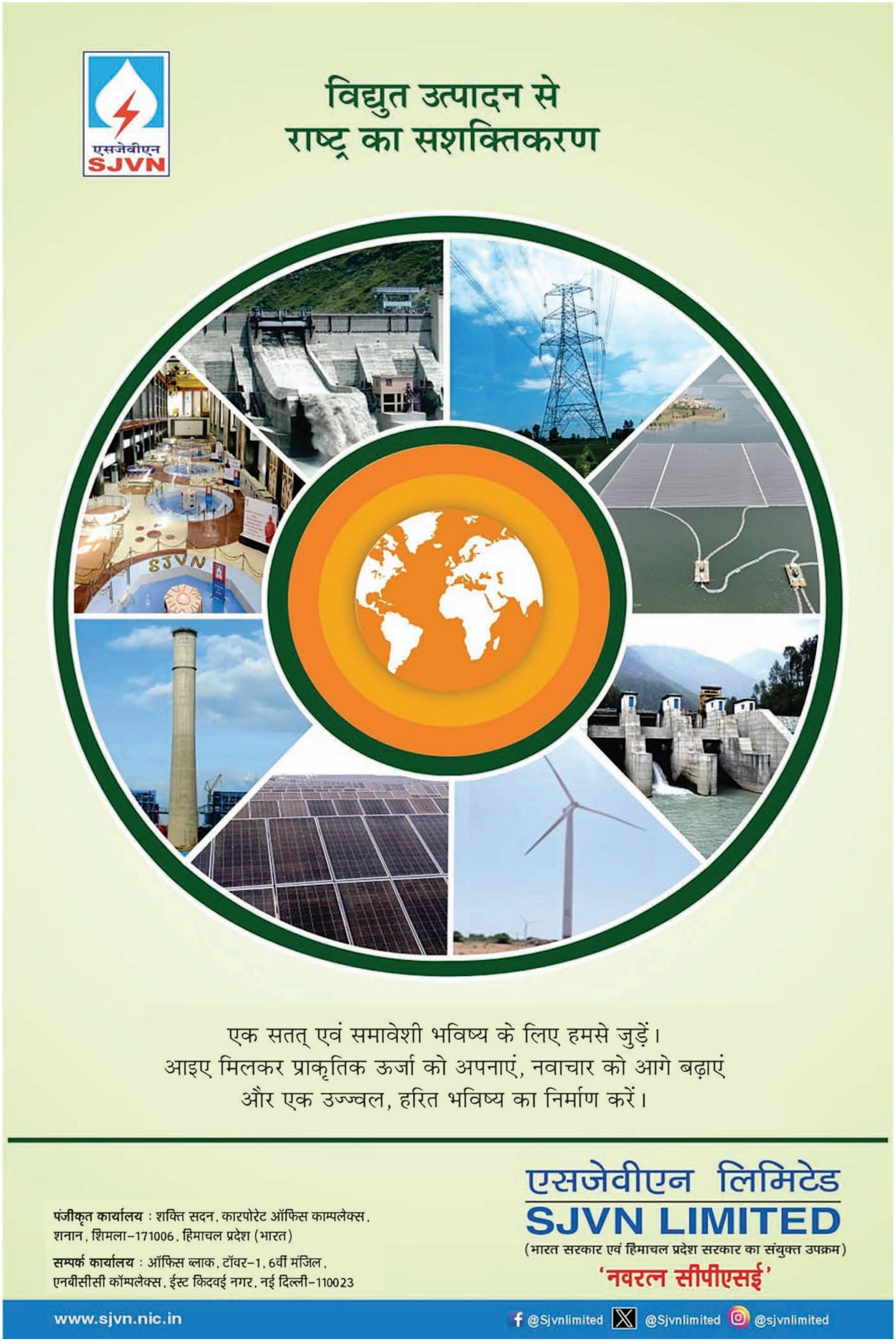

न्यूज ब्रीफ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पोर्ट्स, फिटनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो-2026 का किया दौरा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स, फिटनेस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो-2026 का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगाए गए पवेलियनों में जाकर विभिन्न स्टॉलों पर तैनात प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी एवं जानकारीपूर्ण संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन नीति-निर्माताओं, खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों, उद्योगपतियों, उद्यमियों तथा निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। यह आयोजन भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सार्थक सहयोग को बढ़ावा देते हैं तथा एक सशक्त और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर तथा सांसद अनुराग शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी

भारतेन्दु संवाददाता, भरवाईं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरवाईं में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से एकदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रधानाचार्य निर्मल कुमार ने किया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस अधिकारी प्रवक्ता गणित सुनील कुमार और प्रवक्ता जीव विज्ञान सुरेश कुमारी की देखरेख में हुआ। शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई अभियान चलाया। प्रधानाचार्य निर्मल कुमार ने स्वयंसेवियों को एनएसएस के माध्यम से व्यक्तित्व विकास और समाज सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयंसेवियों को समाज सेवा, सड़क सुरक्षा और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवी को सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। शिविर में 60 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे।

विश्व स्तनपान सप्ताह पर चलेगा जागरूकता अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला शिमला में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार है। अभियान के दौरान माताओं और परिवारों को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने, छह माह तक केवल मां का दूध देने और इसके बाद पूरक आहार शुरू करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। डीसी ने बताया कि जिला की 11 आईसीडीएस परियोजनाओं, 88 पर्यवेक्षक वृत्तों और 2154 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से परामर्श सत्र, गृह भ्रमण, मातृ बैठकें और जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

शिमला निर्माण प्रतिबंध पर भाजपा ने उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शिमला शहर के बड़े हिस्से में प्रस्तावित निर्माण प्रतिबंध को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि यह निर्णय लागू हुआ, तो वर्षों की मेहनत से प्लॉट खरीदने वाले सैकड़ों परिवारों के अपने घर बनाने के सपने प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जीवनभर की कमाई से जमीन खरीदी है और अब आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर मकान बनाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में निर्माण पर रोक लगाना आम नागरिकों के अधिकारों के साथ अन्याय होगा। संदीपनी भारद्वाज ने मांग की कि सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे और स्थानीय लोगों, प्लॉट मालिकों व विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही कोई फैसला ले। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के निष्प्रभावी बनाना उचित नहीं है।

झंडूता में सड़कों के विस्तार को 875 करोड़ का प्रावधान

भारतेन्दु संवाददाता, झंडूता। विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र में सड़क विकास को नई गति मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से थापना से बागछाल, कलोल, भड़ोलियां, शाहतलाई, बड़सर और रंगस तक करीब 93 किलोमीटर लंबी सड़क के विस्तारीकरण, उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए 875 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्यकर्ता संवाद अभियान के तहत कुल्जयार, मलरांव और पपलोआ पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में विधायक ने कहा कि इस परियोजना से कोटधार क्षेत्र के किसानों, बागवानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने कुल्जयार में आग से क्षतिग्रस्त गौशाला का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार को सहायता का आश्वासन दिया।

एचपीएसईबी एम्प्लॉइज यूनियन ने कामेश्वर दत्त को दी भावभीनी विदाई

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। एचपीएसईबी एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा शुक्रवार को हमीरपुर के मटन सिद्ध में यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा के सेवानिवृत्ति अवसर पर एक भव्य एवं गरिमामय राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर प्रदेशभर से आए यूनियन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर श्री कामेश्वर दत्त शर्मा को उनके लगभग 38 वर्षों के उत्कृष्ट, समर्पित एवं निष्कलंक सेवाकाल के लिए भावभीनी शुभकामनाएँ एवं सम्मान अर्पित किया। समारोह के दौरान यूनियन की ओर से उन्हें स्मृति-चिह्न एवं सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज, महासचिव प्रशांत शर्मा, पैट्रन हीरालाल वर्मा तथा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खारवाड़ा ने कामेश्वर दत्त शर्मा की संगठन के प्रति निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्मचारी हितों के लिए किए गए संघर्षपूर्ण एवं उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि उनका अनुभव, नेतृत्व एवं संगठन के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। अपने संबोधन में कामेश्वर दत्त शर्मा ने विभाग, यूनियन के सभी पदाधिकारियों, साथियों एवं कर्मचारियों का वर्षों तक मिले सहयोग, स्नेह एवं विश्वास के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे संगठन एवं कर्मचारी हितों के लिए सदैव अपना सक्रिय सहयोग देते रहेंगे। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष श्री नितीश भारद्वाज एवं महासचिव श्री प्रशांत शर्मा ने बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना की बहाली तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की भी मांग की हैं। समारोह के अंत में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री कामेश्वर दत्त शर्मा के स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल सेवानिवृत्त जीवन की मंगलकामनाएँ करते हुए उनके दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना की।

कांग्रेस संगठन विस्तार में जुटी, शिमला ग्रामीण के 70 से अधिक लोगों ने थामा पार्टी का दामन

छैला–सैंज–यशवंतनगर–राजगढ़ सड़क के उन्नयन को 290 करोड़ मंजूर : विक्रमादित्य

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन विस्तार अभियान के तहत प्रदेशभर में लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ रही है।

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का लगातार विस्तार हो रहा है और इसी कड़ी में 70 से अधिक लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विचारधारा वाली पार्टी है, जो देश और प्रदेश की एकता, विकास और जनहित के लिए समर्पित है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज युवाओं और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आगे आएं। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में शिमला ग्रामीण क्षेत्र विकास के मॉडल के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से लगातार संवाद और प्रयासों के बाद छैला–सैंज–यशवंतनगर–राजगढ़ सड़क के उन्नयन के लिए करीब 290 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि यह सड़क कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू सहित आसपास के बागवानी क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेब और अन्य उत्पादों की ढुलाई इसी मार्ग से होती है। उन्होंने बताया कि विभाग को सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मानसून के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। इस परियोजना से चार से पांच विधानसभा क्षेत्रों के लोगों और विशेष रूप से बागवानों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि बिरादरी क्षेत्र की सड़क परियोजना के लिए भी करीब 60 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा पहले छूटे हुए करीब 16 किलोमीटर सड़क हिस्से के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क संपर्क बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। बारिश और भूस्खलन के बावजूद लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार सड़कों को खोलने में जुटी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 129 जेसीबी मशीनें विभाग की और 270 मशीनें किराये पर लेकर काम कर रही हैं। अन्य मशीनरी सहित करीब 560 मशीनें सड़क बहाली में लगी हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से बंद सड़कों की निगरानी की जा रही है और अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर मार्ग बहाल करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि किसानों और बागवानों की उपज को नुकसान न पहुंचे।

कांग्रेस का अहंकार संवैधानिक संस्थाओं व सशस्त्र बलों के अपमान तक पहुंचा : अनुराग

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर संसदीय मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन करने, निराधार आरोप लगाने तथा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनादर का व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार सत्ता से बाहर रहने के बावजूद अहंकार से मुक्त नहीं हो पाए हैं और लगातार भारतीय सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। अनुराग ने बताया कि उन्होंने लोकसभा के नियम 222 और 223 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक नोटिस देकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा भारतीय सेना और भारतीय पुलिस का मनोबल गिराने का प्रयास किया है। एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या देश की सुरक्षा से जुड़े अन्य अभियान, कांग्रेस के नेता बार-बार उन पर सवाल उठाते रहे हैं और ऐसा कथन करते हैं जिससे देश के विरोधियों को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि अब संसद के भीतर भी कांग्रेस के नेता आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जो संसदीय नियमों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। इसी कारण उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को नियम 222 और 223 के अंतर्गत नोटिस देकर इस आचरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि संसद के भीतर राहुल गांधी देश के गृह मंत्री पर निराधार आरोप लगाते हैं, जबकि प्रियंका गांधी मीडिया के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। संसद से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी मीडिया को भाजपा का समर्थक बताते हैं और देश की पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं।

शिमला में 374 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे

सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करें अधिकारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को बचत भवन में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारी नियमित निरीक्षण करें और योजना से लाभान्वित बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि उनकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी केंद्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार बच्चों को पोषणयुक्त आहार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। जिला में 374 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 40 आंगनबाड़ी कम क्रेच संचालित हैं और 20 नए क्रेच खोलने की स्वीकृति मिली है। अधिकारियों ने बताया कि शिमला जिला में कुल 2154 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 228 के अपने भवन हैं, जबकि 1076 केंद्र किराये के भवनों और 850 केंद्र अन्य विभागों के भवनों में संचालित हो रहे हैं।

60 केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए धन स्वीकृत किया गया है, जिनमें 34 शौचालय तैयार हो चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, विधवा पुनर्विवाह और स्वरोजगार सहायता योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 25 लाभार्थियों को 50 लाख रुपए की सहायता दी गई, जबकि 94 महिलाओं को स्वरोजगार सहायता प्रदान की गई। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 1813 लाभार्थियों के लिए 2.53 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवारों में बेटी के जन्म पर 25 हजार रुपए की एफडी और माता-पिता को बीमा सुविधा देने का प्रावधान है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पेपर लीक पर कड़ी सख्ती, युवाओं के हित में ऐतिहासिक कानून : राकेश ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने लोकसभा द्वारा शिक्षा सुधार तथा सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पारित कानून का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राकेश ने कहा कि लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल, फर्जीवाड़ा तथा तकनीकी माध्यमों से होने वाली धोखाधड़ी जैसी घटनाओं ने लाखों मेहनती युवाओं की आशाओं को आघात पहुंचाया था। अब इस कानून के माध्यम से ऐसे अपराधों में शामिल संगठित गिरोहों, संस्थानों और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी। यह कानून केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, संगठित अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई तथा दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इससे भविष्य में होने वाली विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट, जेईई, सीयूईटी तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को नई मजबूती मिलेगी तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

जोत लागत योजना के रिक्त पद भरने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला/मंडी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जोत लागत अध्ययन (सीसीएस) योजना के कर्मचारियों ने रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर कुलपति प्रो. महावीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रधान नरेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 1973 से संचालित यह योजना किसानों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है, जिनका उपयोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण और कृषि नीतियों में किया जाता है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि योजना के 41 स्वीकृत पदों में से 33 पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे फील्ड कार्य, आंकड़ा संग्रहण और कार्यालयी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों ने नए फसल चक्र वर्ष को देखते हुए जल्द नियुक्तियां करने और योजना के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

पेपर लीक रोकने के लिए बना सख्त कानून, जम्वाल ने पीएम व नड्डा का जताया आभार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए लोकसभा में सख्त कानून पारित किया गया है, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया। बिलासपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि नए कानून में दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को 5000 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। सदर क्षेत्र के लिए 25.45 करोड़ और 10.13 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदर क्षेत्र की संपर्क सड़कों की हालत खराब है और निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री से सड़कों की जांच की मांग की।

'ओबेसिटी मुक्त भारत' संदेश लेकर 30 हजार किमी की बुलेट यात्रा अंतिम चरण में पहुंची

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। देशभर में स्वस्थ जीवनशैली और मोटापामुक्त भारत का संदेश लेकर निकली 23 वर्षीय तापसी उपाध्याय की बुलेट यात्रा हिमाचल प्रदेश पहुंच गई है।

मेरठ से 9 मार्च 2025 को शुरू हुई यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। शिमला पहुंचने पर अभियान का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तापसी उपाध्याय को सम्मानित करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं की यह पहल विकसित भारत-2047 के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। तापसी ने शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर और हिम रश्मि स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों को योग, ध्यान और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने 'ओबेसिटी मुक्त भारत' का संकल्प लिया, जबकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी अभियान का समर्थन किया। तापसी उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता या प्रायोजन के अब तक 27 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 30 हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी की है। हिमाचल के बाद यात्रा उत्तराखंड पहुंचेगी और 15 अगस्त 2026 को दिल्ली में राष्ट्रध्वज को नमन करने के साथ 17 माह लंबे इस अभियान का समापन होगा।

एसपी शिमला के सरकारी आवास खर्च की होगी विशेष ऑडिट जांच

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षक शिमला के साउथवुड स्थित सरकारी आवास पर वर्ष 2022 से 2025 तक हुए मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के खर्च की जांच के लिए तीन सदस्यीय ऑडिट समिति गठित की है। पुलिस मुख्यालय ने एसपी शिमला की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया है। समिति उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो खर्च के स्रोत, स्वीकृति, बजट प्रावधान और धनराशि के उपयोग की जांच करेगी। समिति सभी संबंधित वित्तीय और निर्माण रिकॉर्ड की समीक्षा करेगी तथा यह भी जांचेगी कि खर्च वित्तीय नियमों के अनुरूप हुआ या नहीं। किसी भी अनियमितता या प्रक्रिया उल्लंघन की स्थिति में समिति जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। पुलिस मुख्यालय ने समिति को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

जुन्गा में खुलेगी ज्ञानवर्धक पुस्तकों से सुसज्जित लाइब्रेरी : भूपेंद्र नेगी

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पुलिस प्रथम सशस्त्र वाहिनी जुन्गा परिसर में शीघ्र ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषयों की ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ-साथ डिजिटल अध्ययन संसाधन भी उपलब्ध होंगे।

इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना है। पुलिस प्रथम सशस्त्र वाहिनी जुन्गा के समादेशक भूपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि लाइब्रेरी की स्थापना के लिए बटालियन के एक पुराने भवन का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में लाइब्रेरी में 12 कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को पुस्तकों के अतिरिक्त डिजिटल अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समादेशक ने बताया कि जुन्गा क्षेत्र की 12 पंचायतों के हजारों युवाओं को इस सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से अपेक्षाकृत कम युवा देश और प्रदेश के विभिन्न उच्च पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, जबकि यहां प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। उचित मार्गदर्शन और अध्ययन संसाधनों के अभाव में कई युवा अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जुन्गा तहसील में युवाओं के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह पहल विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

आरोप जोल सप्पड़ हॉस्टल से देहरा कैश फॉर वोट तक, विधायक ने सरकार से मांगे जवाब

मुख्यमंत्री सहित अधिकारी भी जांच के लिए रहें तैयार

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर भ्रष्टाचार के मामले पर जोरदार हमला बोला है। शर्मा ने कहा है कि धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ हुई एफआईआर राज्य सरकार की नियत पर कई सवाल उठ रहे हैं इस सरकार को पता होना चाहिए की समय आने वाला है जब उनकी भी जांच होगी और इन्होंने जो कुछ किया है उसमें इन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए।

आशीष शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता जितनी चाहे मामले दर्ज कर लें डरने वाले नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा के जितने नेताओं के खिलाफ अभी तक मामले दर्ज किए गए हैं उनमें अभी तक किसी भी मामले में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया है। आशीष शर्मा ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि हमीरपुर के जिस निर्माणाधीन बस अड्डे की चर्चा मुख्यमंत्री बहुत करते हैं, उसका टेंडर 36 करोड़ रुपए का हुआ था। लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए की डैविएशन की गई है। यह भी गड़बड़ झाले की 'बू' में शामिल हो रहा है। आशीष ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला आयकर विभाग का बनता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है, वह सब कुछ नियमों के खिलाफ हो रहा है। पुलिस तंत्र भी इसी में लगा हुआ है। जबकि पता उसे भी है कि होना इस मामले में कुछ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मामलों को दर्ज करके प्रदेश सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने का प्रयास कर रही है। मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

सरकार को पता है कि महिलाओं को 1500 रुपए तो वह दे नहीं सकते। उन्होंने कहा कि नौणी विश्वविद्यालय ने सभी तरह के प्रवेश पर 60 फ़ीसदी की फीस वृद्धि करके प्रदेश के युवाओं को जो तोहफा दिया है, वह इसकी नियति को बयां कर रहा है। नौकरियां तो यह सरकार दे नहीं पा रही, लेकिन पढ़ाई करने के लिए भी उन्हें दिक्कतें पेश करने में इस सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो छात्र पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उन पर फीस का बोझ लादकर शुरुआती स्टेज पर ही परेशान करने की जिद इस सरकार ने पाल रखी है। आशीष का कहना है कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में हर छोटी दवा से लेकर कई तरह के मामले मरीज के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं ग्लूकोज नहीं मिल रहा दवाएं है नहीं सिरिंज बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं यह कैसा अस्पताल है जो सब कुछ मरीजों और उनके तीमारदारों से बाहर से खरीदने के लिए कह रहा है उन्होंने यह भी कहा कि देहरा में भाजपा की बीडीसी बनी है कैश फॉर वोट का यहां जो इस्तेमाल हुआ था, उसका जवाब दिया है। क्या वहां कैश फॉर वोट के मामले में मामला दर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता निश्चित रूप में देगी और यह कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में पांच सीटों तक सीमित कर रह जाएगी।

भारतेन्दु Classifieds

नाम परिवर्तन

मैं, गुरजीत सिंह (58 वर्ष) पुत्र बलवंत सिंह, निवासी मकान नं. 149/11 थनेहड़ा, तहसील सदर जिला मंडी हि.प्र. घोषणा करता हूं कि मेरे पासपोर्ट नंबर एन4698617 में मेरा नाम गुरजीत सिंह वासुदेवा के स्थान पर सही नाम गुरजीत सिंह दर्ज किया जाए। गुरजीत सिंह नाम आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस में भी दर्ज है। सभी संबंधित नोट करें।

कार्यालय ग्राम पंचायत चसवाल विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी (हि0 प्र0)

निविदा आमंत्रण सूचना

वर्ष 2026-27 के लिये निविदायें आमंत्रित करने बारे सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत चसवाल वर्ष 2026-27 के लिये विकास कार्यो के निष्पादन हेतु निम्नलिखित निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। 1. रेता क्रेशर प्रति घन मीटर 2 रेता प्लांट प्रति घन मिटर 3 बजरी क्रेशर 20mm प्रति घन मीटर 4 बजरी क्रेशर 40mm प्रति घन मीटर 5 पत्थर प्रति घन मीटर 6 साईन बोर्ड / बोर्ड writting/बोर्ड size2' 3 or 3' 5 7. सीमेंट ढुलाई सरकाघाट से सीमेंट स्टोर तक 8. ईंटे प्रति हजार (abc Grade) 9. शटरिंग स्टील प्लेट प्रति सुकेयर मीटर 10. शटरिंग लकड़ी प्रति running मीटर 11. सरिया 8mm, 10mm, 12mm प्रति किवंटल 12. मशीन (jcb) द्वारा कटान प्रति घंटा 13. सामग्री ढुलान ट्रेक्टर / जीप/अन्य वाहन द्वारा ग्राम पंचायत के समस्त वार्डों में ।**नियम व शर्तें-** (1) निविदादाता के पास अपना पंजीकरण पेन no. GST NO. का होना आवश्यक है। 2 निविदादाता को निविदा अपने लैटर पैड पर ग्राम पंचायत चसवाल के नाम भेजनी होगी । 3. निविदादाता को बिल के साथ मात्रा सहित Valid Transit Pass Form W और जमा करवाने होंगे । 4 सभी करों का लेन-देन सरकार के प्रावधानों अनुसार होगा । 5 सामग्री की आपूर्ति लोक निर्माण विभाग के स्पेसिफिकेशन के अनुशार होगी । 6 दरे अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए। और प्रत्येक सामग्री के साथ GST का भी ब्यौरा देना होगा । 7 निर्माण सामग्री कार्या स्थल सड़क तक उपलब्ध करवानी होगी। 8 पारित निविदादाओं को मुबलिक 20000/- रुपये अग्रिम / सुरक्षित राशी के रूप में जमा करवानी होगी । 9 ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्राधिकार में एक ही मूल्य देये होगा । 10 निविदादाता यदि सप्लाई ऑडर जारी होने उपरान्त निर्धारित अवधि में सामग्री समयानुसार नहीं कर पाता है तो उसकी गत समय दी गई सामग्री की देये राशी का भुगतान नहीं किया जाएगा और न ही अग्रिम/सुरक्षित राशी वापिस की जायेगी । 11 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत / अस्वीकृत करने व सामान दर रहने की स्थिति में एक या एक से अधिक निविदादाओं के लिये कार्य आदेश निर्गत करने सामग्री की गुणवता के चयन तथा निविदा किसी भी समय रद्द करने का अधिकार पंचायत व विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । 12 सामग्री राशी की अदायगी कार्या पूर्ण होंने के उपरांत TA/JE की पमाइश के बाद होगी। तथा बिलों के साथ Valid Transit पास फॉर्म W और X होना जरुरी है अन्यथा बिलों कि अदयागी नहीं होगी । 13 सामग्री लेने का अंतिम मूल्या निर्णय विभाग JUSTIFICATION का पारित निविदादाताओं के साथ NEGOTATION अनुसार / उपरांत किया जाएगा । सप्लायर से मांगी गई पूर्ण सामग्री का ब्यौरा देना होगा। प्रत्येक सामग्री के आगे राशी लिखना अनिवार्या है। । निविदाए दिनांक 10-8-2026 को कार्यालय ग्राम पंचायत चसवाल में पंचायत बैठक में पंचायत कमेटी द्वारा सभी के सामने 12 बजे खोली जायेगी तथा सभी सप्लायर उस दिन उपस्थित रहे। यदि कोई सप्लायर उस दिन अनुपस्थित रहने कि अवस्था में बाद में उसकी कोई भी शिकायत मान्य नही होगी। कुटेशन का सब टोटल मान्य नहीं होगा । निविदायें दिनांक 9-8.2026 तक पंचायत कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद किसी की कोई भी कुटेशन मान्य नही होगी । यदि किसी प्रशासनिक कारणों में इस तिथि को बदलने का अधिकार ग्राम पंचायत चसवाल के पास सुरक्षित रहेगा । इस दशा में सूचना समाचारपत्रों में प्रदर्शित नहीं की जाएगी सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट पर ही प्रदशित की जाएगी।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत चसवाल विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी (हि0 प्र0)

न्यूज शॉर्ट्स

कांवड़ मेले में एसडीआरएफ की सतर्कता से टला हादसा

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। गंगा में स्नान करते समय तेज बहाव में बहे दो युवकों को एसडीआरएफ जवानों ने समय रहते रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। झांसी निवासी 18 वर्षीय सुधीश ठाकुर और बागपत निवासी 28 वर्षीय राहुल को प्राथमिक उपचार भी दिया गया। जवानों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की गई।

बीमार बुजुर्ग के लिए देवदूत बने एसएसबी जवान

भारतेंदु संवाददाता, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के तड़ीगांव में एसएसबी जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग गोपी चंद को दुर्गम पहाड़ी रास्ते से करीब दो किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर ले जाकर सड़क तक पहुंचाया। गांव में युवाओं की कमी के कारण परिजनों को परेशानी हो रही थी। जवानों की मदद से बुजुर्ग को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके लिए ग्रामीणों ने उनका आभार जताया।

पिथौरागढ़ में नाबालिगों से छेड़छाड़ के आरोप में युवक गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, पिथौरागढ़। नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़ एवं गलत हरकत करने का प्रयास करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गंगोलीहाट क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि एक युवक द्वारा उनकी 10 वर्षीय पुत्री एवं 12 वर्षीय भतीजी को जबरन अपने कमरे में बंद कर उनके साथ छेड़छाड़ की और गलत हरकत करने का प्रयास किया गया।

सृष्टि कंडारी मौत मामले में सीएम धामी ने दिए सीबीसीआईडी जांच के आदेश

भारतेंदु संवाददाता,श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल की शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंपने का फैसला लिया। शिक्षिका की मौत के कारणों का पता लगाने और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की जाएगी।

डॉ. मेघना असवाल बनीं पौड़ी की सीएमओ

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। जनपद पौड़ी की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान अब वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघना असवाल के हाथों में होगी। सेवानिवृत्त हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला के स्थान पर उन्होंने शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) का पदभार ग्रहण कर लिया। विकासखंड कल्जीखाल के बड़कोट गांव की मूल निवासी डॉ. मेघना असवाल लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रही हैं।

एसआईआर में असंतुष्ट मतदाताओं को मिलेगा अपील का अधिकार

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अपील व्यवस्था लागू की गई है। यदि कोई मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वह पहले जिलाधिकारी और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की है।

हाईकोर्ट ने यूकेपीएससी का आदेश किया रद्द

असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन भर्ती में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक प्रोफेसर (रसायन) भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में शामिल

◆ **सहायक प्रोफेसर भर्ती विवाद का हुआ समाधान**

अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता नीलम आर्य और सुमन लता पाल ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें सहायक प्रोफेसर रसायन पद के लिए उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर आयोग ने आपत्ति जताई थी। विशेष रूप से नीलम आर्य की कृषि रसायन विषय में पीएचडी को सहायक प्रोफेसर रसायन पद के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था। हालांकि, उनके पास रसायन विषय में परास्नातक की डिग्री मौजूद थी। इसी आधार पर उन्होंने आयोग के फैसले को चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने लिया अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के आवेदन निरस्तीकरण आदेश को उचित नहीं माना। अदालत ने कहा कि अभ्यर्थियों के मामले में नियमों और योग्यता का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को हुए खर्च के रूप में एक लाख रुपये की राशि चार सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

भर्ती प्रक्रियाओं को मिलेगी स्पष्टता और निष्पक्षता

उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला भर्ती प्रक्रियाओं में नियमों की स्पष्टता और निष्पक्षता के लिए अहम माना जा रहा है। आयोग को अब अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। इस फैसले के बाद सहायक प्रोफेसर रसायन भर्ती से जुड़े अन्य अभ्यर्थियों में भी उम्मीद जगी है।

दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी देने का अनुबंध भरने वाले 49 डॉक्टर 'लापता'

ड्यूटी की शर्त पूरी नहीं करने वाले 69 डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में सेवा देने का बांड भरने वाले कई डॉक्टर अब ड्यूटी से गायब हैं। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कम फीस पर मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों से यह बांड भरवाया जाता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे राज्य के सरकारी अस्पतालों में निर्धारित अवधि तक अपनी सेवाएं देंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, कुल 69 बांडधारी डॉक्टरों ने अपनी निर्धारित सेवा पूरी नहीं की है। इनमें 41 एमबीबीएस डॉक्टर और 28 विशेषज्ञ तथा पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुके चिकित्सक शामिल हैं। इन

डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। कॉलेज द्वारा इनकी आरसी काटी गई, लेकिन कई डॉक्टरों से संपर्क नहीं हो पाया।

बताया गया है कि आरसी जारी होने के बाद चार डॉक्टर अपने दिए गए पते पर नहीं मिले, जबकि 45 डॉक्टरों की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अब कॉलेज प्रशासन ऐसे डॉक्टरों को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि बांड की शर्तों का पालन करना सभी डॉक्टरों की जिम्मेदारी है और नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से उत्तराखंड के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा में रियायत देने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि डॉक्टर अपनी सेवाएं उन क्षेत्रों में दें जहां विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। कॉलेज प्रशासन की इस कार्रवाई को बांड व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गैरहाजिरी पर कॉलेज प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि बांड व्यवस्था केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राज्य के लोगों के हितों से जुड़ी हुई है। यदि डॉक्टर बिना कारण सेवा से दूर रहते हैं तो इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है। अब कानूनी नोटिस जारी होने के बाद संबंधित डॉक्टरों से जवाब मांगा जाएगा। उनके जवाब और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस मामले ने एक बार फिर सरकारी मेडिकल शिक्षा और सेवा बांड की प्रभावशीलता को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

11 अगस्त से 11 अक्टूबर तक बंद रहेगी पाताल भुवनेश्वर गुफा

ऑक्सीजन कमी से पाताल गुफा दो माह बंद

भारतेंदु संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा मानसून के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण दो महीने के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद रहेगी। गुफा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, पाताल भुवनेश्वर गुफा को 11 अगस्त से 11 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा।

पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में शामिल है। यह गुफा अपनी अद्भुत प्राकृतिक बनावट, रहस्यमयी संरचना और धार्मिक महत्व के कारण देशभर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस गुफा का संबंध भगवान शिव और अन्य देवी-देवताओं से जुड़ी धार्मिक कथाओं से है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं।

मानसून के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम संबंधी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। भारी नमी, हवा के सीमित प्रवाह और प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक गुफा के अंदर रहना श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।

गुफा दर्शन हुए स्थगित

अधिकारियों के अनुसार, यह कदम किसी असुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा क्षेत्र की धार्मिक और पर्यटन पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुफा बंद रहने के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी की जाएगी। मौसम सामान्य होने और परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए गुफा खोल दी जाएगी।

पर्यटन गतिविधियां होंगी प्रभावित

गुफा बंद होने से कुछ समय के लिए पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय आवश्यक माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन के इस फैसले को उचित बताया है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर आस्था के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान गुफा में प्रवेश करने का प्रयास न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड की धार्मिक विरासत और प्राकृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जनता की जरूरतों के अनुसार होंगे विकास कार्य : डॉ. अग्रवाल

ऋषिकेश विकास के लिए अग्रवाल ने विधायक निधि से की 64 लाख रुपये की घोषणा

भारतेंदु संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश स्थित कैंप कार्यालय में वीरभद्र मंडल के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के लिए विभिन्न विकास कार्यों हेतु लगभग 64 लाख रुपये विधायक निधि से देने की घोषणा की।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश क्षेत्र का संतुलित और निरंतर विकास उनकी प्राथमिकता है। जनता की आवश्यकताओं और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनता की समस्याओं को गंभीरता से उठाएं और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं।

बैठक में मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े जब भी कोई प्रस्ताव या मांग विधायक के समक्ष रखी गई, उन्होंने उसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान की दिशा में कार्य किया।

ऋषिकेश में लगातार सुधार हुए

मंडल महामंत्री पुनीता भंडारी ने कहा कि ऋषिकेश क्षेत्र में सड़कों का विस्तार, बिजली और पानी की बेहतर व्यवस्था तथा स्ट्रीट लाइटों की सुविधा में लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य स्वयं प्रगति की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर मनोरमा, अनिल भगवाधारी, अशोक पासवान, सुशील उनियाल, चमन कौशल, मुन्नी देवी, कुसुम देवी, सुयश मिश्रा, दुर्गा देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

क्षेत्र में कई परियोजनाएं हुईं विकसित

बैठक में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। परियोजना के तहत 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी), 4 बड़े पुल और 12 वे-साइड सुविधाएं विकसित की गई हैं।

कांवड़ यात्रा में रुड़की की सड़कों पर लगा लंबा जाम

भारतेंदु संवाददाता, रुड़की। कांवड़ यात्रा के दौरान रुड़की शहर में शुक्रवार को यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित दिखाई दी। प्रशासन और पुलिस की ओर से लागू की गई विशेष यातायात योजना यात्रियों और स्थानीय लोगों को राहत देने में सफल नहीं हो सकी। सुबह से ही मच्छी चौक, सिविल लाइन बाजार, मेन बाजार और बीटी गंज क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कांवड़ यात्रियों के कई वाहन निर्धारित कांवड़ पटरी मार्ग के बजाय शहर के अंदर प्रवेश करते रहे, जिससे मुख्य सड़कों पर दबाव बढ़ गया। चोपहिया वाहनों और लोडर वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात धीमा हो गया।

बेंगलुरु सम्मेलन में डॉ. काण्डपाल हुए सम्मानित

एफकेसीसीआई ग्लोबल समिट में डॉ. विनय काण्डपाल को मिला विशिष्ट सम्मान

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। ग्राफिक एरा (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), देहरादून के प्रबंधन अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉ. विनय काण्डपाल ने बेंगलुरु में आयोजित एफकेसीसीआई ग्लोबल सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी समिट-2026 में विशिष्ट ज्यूरी पैनलिस्ट के रूप में सहभागिता कर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देश-विदेश के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सतत विकास से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक विकास, प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। डॉ. विनय काण्डपाल ने ज्यूरी पैनलिस्ट के रूप में विभिन्न संस्थानों और उद्योगों द्वारा प्रस्तुत सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी पहलों का मूल्यांकन किया। उनके निष्पक्ष निर्णय, विषय विशेषज्ञता और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता की सभी ने सराहना की।

डॉ. विनय काण्डपाल ने वैश्विक मंच पर बढ़ाया ग्राफिक एरा का मान

कार्यक्रम के दौरान सांसद श्रीमती प्रभा मल्लिकार्जुन और एफकेसीसीआई की अध्यक्ष श्रीमती उमा रेड्डी ने डॉ. विनय काण्डपाल को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. काण्डपाल ने आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हुए प्रो. अभिषेक रंजन और श्री कीर्तन कुमार के सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया।

आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने विकसित किया अम्ल प्रतिरोधी चुंबकीय नैनोकम्पोजिट

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अम्ल-प्रतिरोधी चुंबकीय नैनोकम्पोजिट विकसित किया है, जो अत्यधिक अम्लीय खनन अपशिष्ट जल (लीचेट्स) से रेडियोधर्मी यूरेनियम और दुर्लभ मृदा तत्वों को प्रभावी ढंग से अलग कर उनकी पुनर्प्राप्ति करने में सक्षम है। यह तकनीक प्रदूषित जल के शोधन के साथ-साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी का भी रास्ता खोलती है।

दुर्लभ मृदा तत्व इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, पवन टर्बाइन, रक्षा उपकरण और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि यूरेनियम परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख ईंधन है। खनन अपशिष्ट जल में दोनों तत्व अक्सर एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम की रेडियोधर्मिता और विषाक्तता पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती है।

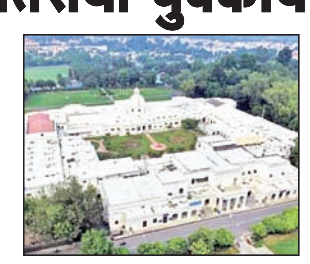

शोधकर्ताओं ने इस चुनौती का समाधान सक्रिय चुंबकीय नैनोकणों के चारों ओर सिलिका का अम्ल-प्रतिरोधी सुरक्षात्मक आवरण विकसित कर किया है। यह परत न केवल नैनोकणों को अत्यधिक अम्लीय वातावरण में संक्षारण से बचाती है, बल्कि उनकी प्रदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता भी बनाए रखती है। खास बात यह है कि इसके निर्माण में पारंपरिक विषैले रसायनों की जगह जैव-अनुकूल अभिकर्मकों का उपयोग किया गया है, जिससे यह तकनीक अधिक सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बन गई है।

देहरादून में भैरव सेना का हल्ला बोल

बदरीनाथ धाम मूर्ति विवाद पर भैरव सेना ने खोला मोर्चा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के लैंसडाउन चौक पर भैरव सेना संगठन ने उत्तराखंड के संवेदनशील मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और माणा गांव में स्थापित विवादित मूर्तियों को जल्द हटाने की मांग की। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने की। संगठन का कहना है कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

भैरव सेना के अनुसार वर्ष 2022 में बदरीनाथ धाम के अंतर्गत आने वाले माणा गांव में कुछ मृतक मानव मूर्तियां स्थापित की गई थीं। संगठन का आरोप है कि सनातन परंपराओं के अनुसार धार्मिक स्थलों पर आराध्य देवी-देवताओं के साथ मानव मूर्तियों की स्थापना उचित नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुका है।

संगठन ने बताया कि वर्ष 2024 में मूर्तियों को हटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने माणा गांव जाने का प्रयास किया था, लेकिन चमोली पुलिस प्रशासन ने उन्हें गौचर में रोक दिया था। बाद में विवाद को सुलझाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन संगठन का आरोप है कि लंबे समय बीतने के बाद भी मूर्तियां नहीं हटाई गई हैं।

आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी

भैरव सेना के केंद्रीय सचिव संजय पवार ने कहा कि यदि तय समय सीमा में विवादित मूर्तियों को नहीं हटाया गया तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने प्रशासन से जनभावनाओं और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने की अपील की। संगठन मंत्री गणेश जोशी ने भी चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। प्रदर्शन में प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष मयंक मलिठा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांवड़ यात्रा | कांवड़ यात्रा के दूसरे दिन हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर गंगे के जयकारों से गूंजे घाट

कांवड़ यात्रा के दूसरे दिन हरिद्वार में गूंजे जयकारे

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। सुबह से ही हरकी पैड़ी सहित गंगा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे कांवड़ यात्री गंगा स्नान कर पवित्र जल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होते रहे। पूरे शहर में हर-हर गंगे और भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दी। कांवड़ यात्रियों के उत्साह और श्रद्धा से हरिद्वार का वातावरण भक्तिमय बना रहा।

कांवड़ यात्रा के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल भरा और अपने क्षेत्रों के लिए प्रस्थान किया। प्रशासन के अनुसार पहले दिन करीब चार लाख कांवड़ यात्री जल लेकर लौटे। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से शिवभक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगाजल लेकर अपने गांवों और शहरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कांवड़ पटरी मार्ग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जहां यात्रियों को प्राथमिक उपचार, दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर भंडारे भी शुरू हो गए हैं, जहां कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है।

हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। भीड़ नियंत्रण, यातायात संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

श्रद्धालुओं का काफिला।

श्रद्धालुओं में बढ़ा विशेष उत्साह और भक्ति

हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुबह से लेकर देर शाम तक कांवड़ यात्रियों की आवाजाही बनी हुई है। गंगा आरती और धार्मिक आयोजनों में भी श्रद्धालुओं की भागीदारी बढ़ी है। शिवभक्त गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के उद्देश्य से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और भक्ति भावना देखने को मिल रही है।

'**कांवड़** यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ने को देखते हुए व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। हरिद्वार में जारी कांवड़ यात्रा श्रद्धा, विश्वास और आस्था का भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रही है। भीड़ नियंत्रण, यातायात संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

-पुलिस प्रशासन

मोहाली से धार्मिक स्थलों के लिए नई बस सेवा होगी शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

सेक्टर-79 स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित 'एक शाम भगवान शिव के नाम' भक्ति संध्या कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार की धार्मिक यात्रा योजना के तहत एक अगस्त से मोहाली से खाटू श्याम, सालासर धाम, ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए नई बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन श्रद्धालुओं को भी धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है, जो आर्थिक या अन्य कारणों से यात्रा नहीं कर पाते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और सरकार इसी भावना के साथ धार्मिक यात्रा योजना का विस्तार कर रही है। नई बस सेवाओं से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और वे बिना किसी परेशानी के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।

भगवंत सिंह मान ने अपने संबोधन में पंजाब की सांझी संस्कृति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती प्रेम, सद्भाव और आपसी सम्मान की पहचान रही है। यहां सभी धर्मों के लोग मिल-जुलकर त्योहार और धार्मिक आयोजन मनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजाब में नफरत फैलाने और समाज को बांटने की कोशिश करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि लोगों से कर के रूप में प्राप्त धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एक अगस्त से मावां धीयां सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं के मोबाइल फोन पर सहायता राशि मिलने के संदेश फिर आने शुरू हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री आवास कूच मामले में तीन हजार पर केस

अमृतपाल सिंह की रिहाई को लेकर प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हजारों समर्थकों और नेताओं पर मामला किया दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सरकारी आवास की ओर कूच करने वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 नामजद नेताओं तथा करीब तीन हजार अज्ञात समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि यह एफआईआर दर्ज होते ही विवादों में घिर गई है, क्योंकि इसमें एक ऐसे पूर्व विधायक का नाम भी शामिल है, जिनका निधन जनवरी 2025 में हो चुका है। इस चूक के सामने आने के बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया और एफआईआर की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

सेक्टर-49 थाना पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब एक बजे वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सेक्टर-50, 51, 44 और 45 के बीच स्थित गोशाला चौक पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया।

पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारी हाथों में तलवारें, फरसे, भाले और डंडे लिए हुए थे। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और बताया कि शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू है, जिसके तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या जुलूस निकालना प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को सेक्टर-25 स्थित रैली ग्राउंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की सलाह भी दी, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ नेताओं ने समर्थकों को

बैरिकेड तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए उकसाया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की तथा हमला किया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तथा आम लोगों के आवागमन में भी रुकावट पैदा की गई। एफआईआर के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के वाटर कैनन वाहन पर चढ़ गए और उसका नोजल तोड़ दिया। वाहन चालक के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई। इस घटना में एएसआई गुरजीत सिंह के हाथ में गंभीर चोट आई, जबकि अन्य कई पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें लगीं।

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 132, 223 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। वीडियो फुटेज, तस्वीरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच एफआईआर में पूर्व विधायक अजीब सिंह मखमैलपुर का नाम शामिल होने से विवाद खड़ा हो गया है।

न्यूज ब्रीफ

बंदरों के आतंक से फेज-11 के लोग परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। मोहाली के फेज-11 में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से 2400 नंबर वाली कोठियों के आसपास बंदरों के झुंड घरों में घुसकर खाने-पीने का सामान और अन्य वस्तुएं उठा ले जाते हैं। निजी स्कूल, पार्क और छात्रावासों के आसपास उनकी मौजूदगी से बच्चों, बुजुर्गों और विद्यार्थियों में भय का माहौल है। पिछले 15 से 20 दिनों से समस्या गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन्यजीव विभाग और नगर निगम दोनों शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है।

दूषित पानी से फैल रहा हेपेटाइटिस-ई का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। मानसून के दौरान दूषित पानी से फैलने वाला हेपेटाइटिस-ई संक्रमण लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। फोर्टिस फेज-8 के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. अरविंद साहनी ने बताया कि यह बीमारी दूषित पानी के सेवन से फैलती है। गर्भवती महिलाओं, लिवर रोगियों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पीलिया, गहरे रंग का मूत्र, थकान, उल्टी और भूख कम लगना इसके प्रमुख लक्षण हैं। विशेषज्ञों ने साफ पानी पीने, स्वच्छ भोजन करने और हाथों की सफाई रखने की सलाह दी है। समय पर जांच और उपचार से संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है।

गमाडा की जनसुनवाई में किसान रखेंगे आपत्तियां

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। गमाडा एरोट्रोपोलिस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों की आपत्तियां सुनने के लिए 3 अगस्त को गांव अजीजपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में सुबह 11 बजे जनसुनवाई होगी। इसमें प्रभावित पक्ष अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सभी दावों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। यह सुनवाई भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत आयोजित की जा रही है। एरोट्रोपोलिस परियोजना से क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

मोहाली सिविल अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीज हुए परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल में दवाओं की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों द्वारा लिखी गई तीन से पांच दवाओं में से मरीजों को केवल एक या दो दवाएं ही अस्पताल की फार्मेसी से मिल रही हैं। बाकी दवाएं उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही हैं। इससे गरीब और बुजुर्ग मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मरीजों ने प्रशासन से सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमित अग्रवाल ने बताया कि कुछ दवाओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है, जो जल्द सामान्य हो जाएगी।

फेज-11 मार्केट में बदहाल सड़क से दुकानदार परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। फेज-11 मार्केट में ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क और पार्किंग की मरम्मत नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के कारण पूरा क्षेत्र कीचड़ और दलदल में बदल गया है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। फेज-10 और फेज-11 को जोड़ने वाली सड़क पर पाइपलाइन डालने के बाद मलबा नहीं हटाया गया। समाजसेवी कैप्टन करनैल सिंह और अकाली नेता गुरदीप सिंह चुघ ने हादसे की आशंका जताते हुए प्रशासन से जल्द सड़क, पार्किंग मरम्मत और सफाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो समस्या और गंभीर हो सकती है।

पुलिस चौकी में थप्पड़ से गई सुनने की क्षमता अदालत ने 20 हजार का दिलाया मुआवजा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पुलिस चौकी में हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के मामले में जिला अदालत ने दोषी इफ्तेकार अहमद पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि पीड़ित मोहम्मद हसन कुरैशी को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। घटना 3 मार्च 2025 की है, जब दोनों के बीच कहासुनी के दौरान इफ्तेकार ने कुरैशी को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। बाद में मेडिकल जांच में पता चला कि कुरैशी के एक कान की सुनने की क्षमता 17 प्रतिशत कम हो गई। डॉक्टर की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इफ्तेकार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(2) के तहत दोषी ठहराया। हालांकि अदालत ने उसे जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा कर दिया। दूसरी ओर, पीड़ित कुरैशी ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा कि 20 हजार रुपये का जुर्माना पर्याप्त नहीं है और वह इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।

मुआवजे से असंतुष्ट पीड़ित करेगा अपील

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक हमला करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि दोषी इफ्तेकार अहमद का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया और यह घटना अचानक हुए विवाद के दौरान हुई थी। इसी आधार पर अदालत ने उसे कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने का निर्णय लिया। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि वह किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, पीड़ित मोहम्मद हसन कुरैशी ने कहा कि एक थप्पड़ के कारण उन्हें स्थायी शारीरिक नुकसान हुआ है, जिसका असर आज भी उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि सुनने की क्षमता कम होने से उन्हें बातचीत करने और सामान्य जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

फ्री पानी और टूटी सड़कों पर नगर निगम सदन में हुआ जोरदार हंगामा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

नगर निगम सदन की शुक्रवार को आयोजित बैठक हंगामे और तीखी राजनीतिक नोकझोंक के बीच संपन्न हुई। बैठक के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर मेयर को घेर लिया। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किए गए 20 हजार लीटर मुफ्त पानी के वादे को प्रमुख मुद्दा बनाया, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शहर की जर्जर सड़कों और विकास कार्यों में हो रही देरी पर सवाल उठाए। दोनों दलों के पार्षदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए बैठक का माहौल पूरी तरह गरमा गया।

कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहरवासियों से किए गए मुफ्त पानी के वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया है। उनका कहना था कि जनता को राहत देने के लिए इस योजना को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। वहीं, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शहर की कई

प्रमुख सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जगह-जगह गड्ढों और टूटी सड़कों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की।

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मेयर ने कहा कि मुफ्त पानी के मुद्दे पर सवाल उनसे नहीं बल्कि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी से पूछे जाने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि सांसद ने चुनाव के दौरान 15 दिनों के भीतर 20 हजार लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। मेयर ने यह भी कहा कि सांसद नगर निगम की बैठकों में शायद ही कभी शामिल होते हैं और उन्हें जनता के सामने अपने वादों का जवाब देना चाहिए।

मेयर ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उसे कांग्रेस की 'बी टीम' करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सवाल नहीं पूछेगी तो पंजाब और चंडीगढ़ में उसका राजनीतिक आधार कमजोर हो जाएगा। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि आम आदमी पार्टी के समर्थन के कारण ही मनीष तिवारी सांसद बन पाए थे।

ट्राईसिटी को मिलेगा नया परिवहन विकल्प अगस्त में शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

ट्राईसिटी के लोगों को जल्द ही टैक्सी सेवा का एक नया और किफायती विकल्प मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी भारत टैक्सी सेवा अगस्त के दूसरे सप्ताह में चंडीगढ़ से शुरू होने की तैयारी में है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य टैक्सी चालकों को बेहतर आय, सामाजिक सुरक्षा और यात्रियों को पारदर्शी तथा सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और बड़ी संख्या में चालक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, ट्राईसिटी यानी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के लगभग 11 हजार टैक्सी चालकों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन नए चालक भी इस सहकारी मॉडल का हिस्सा बन रहे हैं। परियोजना को सफल बनाने के लिए उन्नति कोऑपरेटिव और सहकार भारती मिलकर पंजीकरण, प्रशिक्षण, दस्तावेजों के सत्यापन तथा अन्य

औपचारिकताएं पूरी करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लॉन्चिंग से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ताकि सेवा शुरू होने के साथ ही यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके।

सूत्रों के अनुसार, भारत टैक्सी सेवा का औपचारिक शुभारंभ चंडीगढ़ के सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उनके कार्यक्रम की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के भी कार्यक्रम में मौजूद रहने की संभावना है।

भारत टैक्सी केवल पारंपरिक टैक्सी सेवा तक सीमित नहीं रहेगी। इस प्लेटफॉर्म से ई-रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को भी जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर के भीतर कम दूरी की यात्रा के लिए लोगों को सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे अंतिम छोर तक यातायात की सुविधा मजबूत होगी और यात्रियों को छोटे सफर के लिए भी आसानी से वाहन उपलब्ध हो सकेंगे।

भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली-एनसीआर में की गई थी। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट सहित कई शहरों में भी यह सेवा शुरू हो चुकी है। अब चंडीगढ़ को इस राष्ट्रीय नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जा रहा है। भविष्य में इस सेवा का विस्तार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों तक करने की योजना है।

भारत टैक्सी को देश का पहला सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। यह मॉडल निजी एग्रीगेटर कंपनियों जैसे ओला और उबर से अलग है। इसमें टैक्सी चालकों से भारी कमीशन नहीं लिया जाएगा।

बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाली दो महिलाएं हुईं गिरफ्तार

- पुलिस ने 10 मोबाइल और कई सिम कार्ड किए बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। यूटी पुलिस के साइबर क्राइम थाने ने क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली के उत्तम नगर से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिलाएं खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देती थीं और उनकी गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल कर लाखों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम देती थीं। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए हैं।

यह कार्रवाई एसपी साइबर गीतांजलि खंडेलवाल के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार, इस मामले में 30 जून को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे एसबीआइ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर फोन आया। कॉल करने वाली महिला ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए ओटीपी, सीवीवी और कार्ड से जुड़ी अन्य गोपनीय जानकारी हासिल कर ली। इसके कुछ ही समय बाद शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड से करीब 1.92 लाख रुपये के अनधिकृत लेनदेन कर दिए गए।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रेल के आधार पर दिल्ली के उत्तम नगर स्थित एक किराये के मकान पर छापा मारा, जहां से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि गिरोह का एक अन्य सदस्य उन्हें लोगों का मोबाइल नंबर और बैंक संबंधी डाटा उपलब्ध कराता था, जिसके आधार पर वे लोगों को फोन कर ठगी करती थीं।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं में से एक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दूसरी से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है।

दुर्घटना के दस साल बाद परिवार को मिला न्याय और मुआवजा

ट्रिब्यूनल ने आर्मी ट्रक चालक को दोषी मानते हुए रक्षा मंत्रालय को 35.86 लाख रुपये मुआवजा देने के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक किसान के परिवार को करीब दस वर्ष बाद न्याय मिला है। चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने वर्ष 2016 में हुए एक सड़क हादसे में मृतक किसान के परिजनों को 35.86 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने हादसे के लिए सेना के ट्रक चालक को जिम्मेदार ठहराते हुए रक्षा मंत्रालय को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, 13 मई 2016 को जालंधर जिले के शाहकोट क्षेत्र में बलवंत सिंह अपनी महिंद्रा बोलेरो कार से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। गाय को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन पीछे से तेज गति से आ रहे सेना के एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर

इतनी भीषण थी कि बलवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद राहगीर बलजिंदर सिंह ने उन्हें तत्काल शाहकोट के सदाना अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जालंधर के घई अस्पताल रेफर किया गया, जहां अगले दिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक के बेटे गोबिंदप्रीत सिंह ने चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में सेना के ट्रक चालक हरजिंदर सिंह और रक्षा मंत्रालय के खिलाफ मुआवजे की याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि उनके पिता की मौत ट्रक चालक की तेज और लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई। उन्होंने बताया कि बलवंत सिंह की उम्र

ट्रिब्यूनल ने दिलाया किसान परिवार को न्याय

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय प्रत्येक चालक का दायित्व है कि वह आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखे और परिस्थितियों के अनुसार गति नियंत्रित रखे। यदि चालक समय रहते वाहन पर नियंत्रण रखता तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि सेना के ट्रक चालक ने आवश्यक सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण यह दुखद हादसा हुआ। सुनवाई के दौरान मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया गया। परिवार ने बताया कि बलवंत सिंह खेती के माध्यम से पूरे परिवार का भरण-पोषण करते थे और उनकी असमय मृत्यु से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। परिवार को कई वर्षों तक न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की राशि तय करते समय मृतक की आयु, आय, आश्रितों की संख्या और सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित मानकों को आधार बनाया।

हादसे के समय 47 वर्ष थी और वह खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिवार ने दावा किया कि उनकी मासिक आय लगभग एक लाख रुपये थी और इसी आधार पर एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गई।

वहीं, सेना की ओर से पेश अधिवक्ता ने ट्रिब्यूनल में दलील दी कि हादसे के लिए स्वयं बलवंत सिंह जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने अचानक ब्रेक लगाए थे। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना का मुख्य कारण सेना के ट्रक चालक की लापरवाही थी।

पंचकूला कोर्ट को मिली बम धमकी सुरक्षा एजेंसियां हुईं अलर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

सेक्टर-1 स्थित पंचकूला जिला न्यायालय परिसर को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंच गईं। पूरे न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने परिसर में आने-जाने वाले लोगों की जांच भी तेज कर दी।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10:35 बजे जिला न्यायालय परिसर को लेकर सुरक्षा संबंधी अलर्ट प्राप्त हुआ। सूचना मिलते ही मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। इसके बाद पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। न्यायालय परिसर के प्रत्येक हिस्से की गहन जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

सुरक्षा एजेंसियों ने न्यायालय भवन, पार्किंग क्षेत्र, प्रवेश और निकास द्वार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष निगरानी रखी। परिसर में मौजूद न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है और हर गतिविधि पर सतर्कता से निगरानी की जा रही है।

धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए। बम निरोधक दस्ते और अन्य विशेषज्ञ

टीमों ने परिसर की बारीकी से जांच की। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही हैं।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन तथा पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। लोगों से शांति बनाए रखने तथा सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

कनाडा में पंजाब के छात्रों ने शुरू किया प्रदर्शन

पीजी वर्क परमिट खारिज होने से परेशान भारतीय छात्र कर रहे हैं तीन सप्ताह से प्रदर्शन

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी शहर में पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) के आवेदन खारिज होने के विरोध में करीब एक हजार भारतीय छात्र पिछले तीन सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या पंजाब के छात्रों की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, लगभग 500 छात्र पंजाब से हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों ने 29 जुलाई से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। खराब मौसम, बारिश और तेज धूप के बावजूद छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं और कनाडा सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं।

छात्रों का कहना है कि उन्होंने कनाडा में शिक्षा हासिल करने के लिए लाखों रुपये खर्च किए थे। दाखिले के समय कॉलेजों की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि कोर्स पूरा करने के बाद वे पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए योग्य होंगे। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिए गए कि उनके कोर्स अब मान्यता योग्य नहीं माने जा रहे हैं।

प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल है कि जब प्रवेश के समय उनके कोर्स मान्य थे और उन्हें उसी आधार पर कनाडा भेजा गया, तो बाद में नियमों में बदलाव कर उनके भविष्य को संकट में क्यों डाल दिया गया। छात्रों का कहना है कि अचानक बदले नियमों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।

कई छात्रों ने बताया कि उनके परिवारों ने उन्हें विदेश भेजने के लिए जमीनें बेचीं या भारी कर्ज लिया। लाखों रुपये खर्च करने के बाद अब जब उन्हें वर्क परमिट नहीं मिल रहा है तो वे न तो नौकरी कर पा रहे हैं और न ही अपने भविष्य को लेकर कोई योजना बना पा रहे हैं। कई छात्र मानसिक तनाव और चिंता से गुजर रहे हैं। कुछ छात्र अपने परिवारों को भी पूरी स्थिति बताने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार आर्थिक संकट में आ जाएगा।

छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्क परमिट आवेदन रद्द होने के बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो गई है। कई छात्रों का कानूनी स्टेटस मुश्किल में पड़ गया है। कुछ के हेल्थ कार्ड रद्द होने की बात सामने आई है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं लेने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने और काम करने की अनुमति नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। कई छात्रों को अब कनाडा से वापस भेजे जाने का डर भी सता रहा है।

इस मुश्किल समय में कैलगरी स्थित स्थानीय गुरुद्वारा साहिब छात्रों की मदद के लिए आगे आया है। गुरुद्वारा प्रबंधन ने जरूरतमंद छात्रों के लिए लंगर, राशन और रहने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। प्रबंधन ने छात्रों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह का गलत कदम न उठाएं।

वहीं, इमिग्रेशन मामलों के जानकारों ने प्रभावित छात्रों को कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्र दोबारा आवेदन करने से पहले इमिग्रेशन विभाग से अपने मामलों की दोबारा समीक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित समय सीमा के भीतर फेडरल कोर्ट में अपील करने का विकल्प भी उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों में नए कोर्स के विकल्प पर भी विचार करें।

इस पूरे विवाद का सबसे ज्यादा असर पंजाब के छात्रों पर पड़ रहा है। प्रभावित छात्रों में जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर और कपूरथला सहित कई जिलों के विद्यार्थी शामिल हैं। इन परिवारों ने अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए 15 से 25 लाख रुपये तक खर्च किए हैं या कर्ज लिया है।

एलएडीसी नीति के विरोध में वकीलों का आंदोलन जारी

सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) नीति के विरोध में पंजाब भर के अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन लुधियाना के नेतृत्व में 25वें दिन भी 'नो वर्क' पूरी तरह प्रभावी रहा। अधिवक्ताओं की हड़ताल और भूख हड़ताल के कारण जिला अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ। कई मामलों में केवल अगली तारीखें ही दी गईं।

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विपन सग्गड़ और महासचिव एडवोकेट हिमांशु वालिया ने कहा कि एलएडीसी नीति के खिलाफ संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता और नीति वापस नहीं ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष मार्च निकालकर अपनी मांगें दोहराईं। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल वकीलों के हितों का मामला नहीं है, बल्कि कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है।

आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। पूर्व कांग्रेस विधायक संजय तलवाड़, पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और पूर्व विधायक कुलदीप वैद ने धरना स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं को समर्थन दिया। नेताओं ने कहा कि वकीलों की मांगें जायज हैं और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को संसद तक उठाया जाएगा।

वहीं, जिला बार एसोसिएशन ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि आंदोलन जारी रहने तक समय सीमा वाले मामलों को छोड़कर नए मामलों की फाइलिंग नहीं की जाएगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एलएडीसी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एलएडीसी की नियुक्ति करेंगे। किसी भी एलएडीसी को सीधे जेल में बंद आरोपी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेने की अनुमति नहीं होगी।

उधर, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ बार एसोसिएशंस ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। कमेटी ने 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

मनोरंजन कालिया ग्रेनेड हमले की साजिश हुई नाकाम बीकेआई नेटवर्क के दो आतंकी गिरफ्तार

पाकिस्तानी नेटवर्क से मिले हथियारों की सप्लाई चेन खंगाल रही पुलिस

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमला करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए जालंधर पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े आतंकी नेटवर्क के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपितों को उपलब्ध कराए गए हथियार पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेटवर्क के जरिए पंजाब तक पहुंचाए गए थे। पुलिस अब हथियारों की सप्लाई चेन और सीमा पार बैठे लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

सीआईए स्टाफ ने गिरफ्तार आरोपितों की पहचान नकोदर के गांव मुज्जफरपुर निवासी विशाल कुमार और मानवजीत सिंह के रूप में की है। दोनों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि उनके पास से बरामद दोनों पिस्टल पाकिस्तानी तस्करों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई थीं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार किस माध्यम से भारत पहुंचे और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं।

जांच एजेंसियों के अनुसार, दोनों आरोपित पिछले करीब एक महीने से जालंधर के दो प्रमुख वीआईपी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उन्होंने संबंधित लोगों की दिनचर्या, आने-जाने के रास्तों और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी जुटा ली थी। पुलिस का मानना है कि यदि समय रहते आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो प्रदेश में बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपितों को जालंधर के अलावा अमृतसर और पटियाला में भी अलग-अलग वारदातों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी। आतंकी संगठन का उद्देश्य पंजाब में डर और अस्थिरता का माहौल पैदा करना बताया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लों की निगरानी में एसीपी अमरबीर सिंह और सीआईए स्टाफ प्रभारी सुरिंदर सिंह की टीम ने भगत सिंह कॉलोनी के पास कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया।

अमृतसर में डेंगू रोकथाम के लिए प्रशासन हुआ सतर्क

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने रोकथाम की तैयारियां तेज कर दी हैं। नेशनल डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जिला प्रशासनिक परिसर में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पल्लवी शर्मा ने की।

बैठक में हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष निगरानी और सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग सहित नगर निगम, शिक्षा विभाग, वाटर सप्लाई, पंजाब रोडवेज, मेडिकल कॉलेजों और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी विभागों को डेंगू रोकथाम के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पल्लवी शर्मा ने कहा कि डेंगू सीजन को देखते हुए जागरूकता अभियान तुरंत शुरू किया जाए और प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस बढ़ाई जाए।

पद नहीं संगठन के प्रति वफादारी है महत्वपूर्ण : वड़िंग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से पंजाब की राजनीति में चर्चा हुई तेज

भारतेंदु संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। फतेहगढ़ साहिब में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की अगुवाई में आयोजित बैठक के दौरान राजा वड़िंग ने कहा कि उनके लिए अध्यक्ष पद कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पार्टी के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी निभाना है।

राजा वड़िंग ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में पार्टी उनका टिकट भी काट देती है, तब भी वह कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका जुड़ाव पद से नहीं बल्कि संगठन और विचारधारा से है।

उन्होंने कहा कि वह चार बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अध्यक्ष पद उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई नेता अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करने की अपील की।

अध्यक्ष पद पर बयान के बाद कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल

राजा वड़िंग ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बदलते चुनावी दौर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले युद्ध बंदूक और टैंकों से लड़े जाते थे, लेकिन अब ड्रोन का समय है। इसी तरह राजनीति और चुनाव भी बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव मोबाइल और डिजिटल माध्यमों से लड़े जा रहे हैं। फर्जी खबरों का प्रभाव बढ़ गया है, इसलिए पार्टी को समय के साथ बदलना होगा।

राजा वड़िंग के बयान को राजनीतिक हलकों में उनके अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

सड़क हादसे के बाद राइडर पर दातर से वार

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू स्थित राम मंदिर के पास वीरवार देर शाम एक मामूली सड़क टक्कर के बाद कुछ युवकों ने जेप्टो राइडर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर की हड्डी टूट गई। घायल की पहचान गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू निवासी विनय सेठ के रूप में हुई है। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, विनय सेठ अपनी बाइक पर डिलीवरी देने के लिए राम मंदिर के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक एक कार से टकरा गई। आरोप है कि इसके बाद कार सवार युवकों ने जानबूझकर उसकी बाइक को टक्कर मारकर उसे सड़क पर गिरा दिया। जैसे ही विनय नीचे गिरा, कार से तीन से चार युवक बाहर निकले और उस पर हमला कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने युवक को संभलने का मौका तक नहीं दिया और दातर से उसके सिर पर कई वार किए। हमले के कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने से वह मौके पर बेहोश हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई।

पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को मिलेगा संतुलित आहार

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का नया मेन्यू हुआ जारी

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसाइटी ने पीएम पोषण योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन का नया साप्ताहिक मेन्यू जारी कर दिया है। यह नया मेन्यू 1 जुलाई से लागू किया गया है। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को तय मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाया जाए।

जारी आदेशों में कहा गया है कि स्कूलों में विद्यार्थियों को कतार में बैठाकर मिड-डे मील इंचार्ज की निगरानी में खाना खिलाया जाए। भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था की जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख की होगी।

नए मेन्यू के अनुसार सोमवार को विद्यार्थियों को दाल और रोटी परोसी

जाएगी। मंगलवार को राजमा-चावल और खीर दी जाएगी। बुधवार को आलू मिलाकर काले या सफेद चने के साथ पूरी या रोटी उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुवार को आलू और प्याज के पकौड़ों वाली कढ़ी के साथ चावल दिए जाएंगे। शुक्रवार को मौसमी सब्जी और रोटी का प्रावधान रखा गया है। शनिवार को साबुत माह की दाल, चावल और मौसमी फल दिए जाएंगे। इसके अलावा अतिथि भोजन योजना के तहत गांव के सरपंच, दानदाताओं और अन्य गणमान्य लोगों के सहयोग से विशेष अवसरों पर विद्यार्थियों को अतिरिक्त पौष्टिक भोजन, फल या मिठाई उपलब्ध करवाने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का उद्देश्य बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना है।

कानून व्यवस्था मजबूत करने को पुलिस ने कसी कमर

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर।

नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर सतिंद्र सिंह ने शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय कर दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी गंभीर आपराधिक घटना या लापरवाही पर संबंधित अधिकारी और एसएचओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने रात की गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी सड़कों पर स्पष्ट दिखनी चाहिए, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़े और अपराधियों में भय बना रहे।

गुरदासपुर में बंद सैलून के शटर पर अज्ञात आरोपी ने चलाई गोली

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। गांव फज्जुपुर में एक बंद सैलून के शटर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सैलून मालिक मनोहर मसीह ने बताया कि हड़ताल के कारण दुकानें बंद थीं। वह सुबह करीब 8 बजे दुकान पर पहुंचे थे और सफाई करने के बाद लगभग 9 बजे वहां से चले गए थे।

उन्होंने बताया कि शाम करीब 5 बजे जब वह दोबारा दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैलून का शटर हिला हुआ था और अंदर लगा शीशा भी टूटा हुआ था। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब उन्होंने दुकान के अंदर जाकर जांच की तो वहां गोली का एक खोल मिला।

इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम

मौके पर पहुंची और गोली के खोल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके।

सैलून मालिक मनोहर मसीह ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि गोली बंद दुकान के शटर पर चलाई गई है और यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वारदात किस समय हुई।

लुधियाना में 10 करोड़ का प्रॉपर्टी घोटाले में जाली दस्तावेजों से महिला की जमीन पर लिया लोन

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। महानगर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति हड़पने और उस पर भारी भरकम ऋण लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक महिला की कीमती संपत्ति को जाली हस्तांतरण पत्र के माध्यम से अपने नाम करवा लिया और बाद में उसी संपत्ति को गिरवी रखकर 10 करोड़ रुपये का ऋण ले लिया।

पीड़िता नैन्सी जिंदल की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने संजीव कुमार, हेमंत कुमार, संजीव कौशल और कविता गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

शिकायत के अनुसार आरोपी संजीव कुमार और उसकी पत्नी कविता गुप्ता ने मिलकर साजिश रची। आरोप है कि संजीव कुमार ने फर्जी हस्तांतरण पत्र तैयार करवाकर पीड़िता की संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम दर्ज करवा दिया। इसके बाद राजस्व विभाग से इंतकाल संख्या 18069 को भी अपने पक्ष में मंजूर करवा लिया गया।

आरोपियों ने संपत्ति को कागजों में अपने नाम करवाने के बाद उसे गिरवी रखकर टाटा कैपिटल से 10 करोड़ रुपये का ऋण हासिल कर लिया। जब पीड़िता को इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की।

पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार इस मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और संपत्ति से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने में किन लोगों की मदद ली गई और ऋण प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल था। वहीं पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।

खुलासा | अजनाला से गिरफ्तार आरोपितों पर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों के लगाए आरोप

स्वतंत्रता दिवस पर हमले की साजिश विफल, चार गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी वारदात को अंजाम देने की कथित साजिश को अमृतसर देहात पुलिस ने नाकाम करते हुए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह अजनाला क्षेत्र से इन आरोपितों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी पहले भी पुलिस ठिकानों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं।

पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपितों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर गतिविधियां संचालित करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 23 जुलाई की रात को सीमावर्ती क्षेत्र अजनाला की पुलिस चौकी चमियारी पर बोतल बम फेंकने की घटना में भी इनकी भूमिका सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली थी। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने चौकी पर हमले की पुष्टि करने से इनकार किया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन आरोपितों का किन अन्य घटनाओं से संबंध रहा है।

पुलिस को संदेह है कि हाल ही में एएसआई जोगा सिंह की हत्या और आर्मी क्षेत्र खासा के बाहर हुए धमाके जैसी घटनाओं में भी इसी गिरोह की भूमिका हो सकती है। फिलहाल इन मामलों में आरोपितों की संलिप्तता की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

आईएसआई कनेक्शन की जांच में जुटी अमृतसर देहात पुलिस

अमृतसर देहात पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रमदास निवासी करणबीर सिंह, मनदीप सिंह, सुखदीप सिंह और प्रदीप सिंह के रूप में की है। पुलिस का कहना है कि चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी में है। रिमांड के दौरान उनसे हथियारों, विस्फोटक सामग्री की व्यवस्था, नेटवर्क और विदेशी संपर्कों को लेकर पूछताछ की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की आतंकी साजिश को विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

शनिवार का धार्मिक महत्व: भगवान शनि देव की पूजा, कर्म और न्याय का गहरा संदेश

निर्मल रानी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

शनिवार का दिन भारतीय धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। यह दिन मुख्य रूप से भगवान शनि देव को समर्पित माना जाता है। हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। मान्यता है कि शनिवार के दिन श्रद्धा और विधि विधान से शनि देव की पूजा करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन तथा सफलता प्राप्त होती है।

भारतीय संस्कृति में सप्ताह के प्रत्येक दिन का संबंध किसी न किसी देवी देवता से माना गया है। उसी प्रकार शनिवार का संबंध भगवान शनि से जुड़ा हुआ है। शनि देव को सूर्य देव और माता छाया का पुत्र माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि देव की दृष्टि बहुत प्रभावशाली होती है। वे व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करके उचित फल देते हैं। इसलिए शनिवार को लोग शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, दान और सेवा कार्य करते हैं।

भगवान शनि देव का धार्मिक स्वरूप: भगवान शनि देव को कर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर परिणाम देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी और सदाचार के मार्ग पर चलता है तो शनि देव उसकी उन्नति में सहायक होते हैं। वहीं गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को शनि देव कठिन परिस्थितियों के माध्यम से सुधारने का अवसर देते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार शनि देव का वाहन कौआ है और उनका रंग काला माना जाता है। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने की परंपरा है। इसमें काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं और सरसों का तेल प्रमुख माने जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इन वस्तुओं का दान करने से शनि से जुड़े दोषों का प्रभाव कम होता है।

शनिवार की पूजा का महत्व: शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शनि देव की पूजा करने की परंपरा है। भक्त शनि मंदिरों में जाकर भगवान शनि को तेल अर्पित करते हैं और दीपक जलाते हैं। कई लोग शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है और शनिवार को इसकी पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं।

शनि देव की पूजा में शनि मंत्रों का जाप भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त श्रद्धा के साथ शनि देव का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की कामना करते हैं। पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म करना भी शनि उपासना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है।

शनि और कर्म का संबंध: भारतीय दर्शन में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है क्योंकि वे व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार परिणाम प्रदान करते हैं। शनिवार हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और ईमानदारी आवश्यक है।

कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें व्यक्ति की परीक्षा माना जाता है। शनि देव का प्रभाव व्यक्ति को संघर्षों से लड़ना और मजबूत बनना सिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ कठिन समय का सामना करता है वह आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है।

शनिवार को किए जाने वाले धार्मिक कार्य: शनिवार के दिन कई धार्मिक कार्यों को शुभ माना जाता है। इनमें प्रमुख हैं,शनि देव की पूजा करना,सरसों के तेल का दीपक जलाना,काले तिल का दान करना, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, पशु पक्षियों को भोजन कराना, पीपल के पेड़ की पूजा करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार को सेवा और दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

पत्रकारिता विचारधारा का प्रचार नहीं बल्कि जनता तक सत्य पहुंचाने का माध्यम होनी चाहिए

सुभाष चंद काशव
गांव, जौवा, जिला चंबा

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जाता है। इसका मूल दायित्व सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज बनना और निष्पक्ष तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है, किंतु आज भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से की कार्यशैली को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता को लेकर जारी होने वाली रिपोर्टों में भारत की स्थिति को लेकर व्यक्त की गई चिंताएं भी इसी ओर संकेत करती हैं कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर बहस पहले से अधिक प्रासंगिक हो चुकी है।

पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हुई है। जहां एक ओर अनेक टीवी चैनलों पर राजनीतिक ध्रुवीकरण, आक्रामक बहसों और टीआरपी-केंद्रित प्रस्तुति के आरोप लगते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने वैकल्पिक सूचना माध्यम के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में दर्शक समाचारों और विश्लेषण के लिए यूट्यूब तथा अन्य डिजिटल मंचों की ओर रुख कर रहे हैं। हाल ही में एक प्रमुख टीवी एंकर द्वारा यूट्यूब आधारित शिक्षकों और ऑनलाइन एजुकेटर्स के बारे में की गई टिप्पणी ने व्यापक विवाद को जन्म दिया। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और अनेक शिक्षकों, छात्रों तथा कंटेंट क्रिएटर्स ने इसे अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना बताया।

दरअसल, डिजिटल युग में शिक्षा, सूचना और संवाद के नए माध्यमों को पूरी तरह खारिज कर देना न तो व्यावहारिक है और न ही उचित। यूट्यूब जैसे मंचों ने लाखों विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से हर मंच पर गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रश्न बना रहता है, लेकिन किसी पूरे वर्ग को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना स्वस्थ सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार समाज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर मीडिया की भाषा और दृष्टिकोण को लेकर भी समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। उत्तराखंड के एक जिम संचालक से जुड़े मामले में भी कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने सहायता की अपील की, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया।

इस घटना ने यह दिखाया कि सोशल मीडिया केवल विवाद और नकारात्मकता का मंच नहीं है, बल्कि वह सामाजिक सहयोग और मानवीय एकजुटता का माध्यम भी बन सकता है। दूसरी ओर, जब किसी व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों का उपहास किया जाता है, तो उससे पत्रकारिता की गरिमा पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

पत्रकारिता का उद्देश्य किसी विचारधारा, राजनीतिक दल या समूह का प्रचारक बनना नहीं, बल्कि तथ्यों को सामने लाना और जनता को सूचित करना है। दुर्भाग्य से कई बार कुछ मीडिया मंचों पर तथ्यों के स्थान पर उत्तेजना, आरोप-प्रत्यारोप और सनसनीखेज प्रस्तुति को प्राथमिकता दी जाती है। इससे न केवल मीडिया की साख प्रभावित होती है, बल्कि दर्शकों का भरोसा भी कमजोर पड़ता है। यही कारण है कि आज मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर व्यापक बहस हो रही है। हालांकि यह भी सच है कि संपूर्ण पत्रकारिता जगत को एक ही पैमाने से नहीं आंका जा सकता।

आज भी अनेक पत्रकार ऐसे हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों ने ऐसे पत्रकारों को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का अवसर प्रदान किया है। यही लोकतंत्र की ताकत भी है कि विविध विचारों और स्वतंत्र आवाज़ों के लिए जगह बनी रहती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

‘**हमेशा** याद रखें कि आपका अपना संकल्प ही आपकी सफलता का आधार है ‘

-अब्राहम लिंकन

संपादकीय

बेटियों की सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी

महिलाएं किसी भी समाज की आधारशिला होती हैं। एक विकसित और प्रगतिशील समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त हैं। आज के आधुनिक दौर में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, व्यापार और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बावजूद महिला सुरक्षा आज भी समाज के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि यह पूरे समाज की सोच, जिम्मेदारी और संस्कारों से जुड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा का अर्थ केवल अपराधों से बचाव नहीं बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां महिलाएं बिना डर के अपने निर्णय ले सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, रोजगार कर सकें और समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकें। जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं तो वे अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर पाती हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

आज महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, साइबर अपराध और अन्य प्रकार की हिंसा महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाएं न केवल पीड़ित महिला को मानसिक और शारीरिक पीड़ा देती हैं बल्कि समाज में असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि कानूनों का प्रभावी पालन और समाज की सकारात्मक सोच भी जरूरी है। महिला सुरक्षा की शुरुआत परिवार से होती है। परिवार बच्चों को जो संस्कार और सोच देता है वही आगे चलकर समाज का रूप लेती है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को समानता, सम्मान और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना जरूरी है। बेटियों को कमजोर समझने की सोच को बदलना होगा और बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा। परिवार में समान व्यवहार से ही एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है।

शिक्षा महिला सुरक्षा का सबसे मजबूत माध्यम है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम होती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास देती है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इसलिए हर लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी महिला सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो वे अपने जीवन के फैसले अधिक स्वतंत्रता से ले सकती हैं। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर महिलाओं को आत्मविश्वास देते हैं। आज बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रही हैं और समाज की सोच में बदलाव ला रही हैं।

तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को परेशान करने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में डिजिटल जागरूकता और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार की जानकारी जरूरी है। महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी होनी चाहिए और अपराध होने पर तुरंत शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून और योजनाएं लागू की गई हैं। महिला हेल्पलाइन, सुरक्षा अभियान, कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन प्रयासों की सफलता तभी संभव है जब समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अपराध रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ आम नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। बाजार, सड़क, सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। इसके लिए बेहतर प्रकाश व्यवस्था, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और संवेदनशील प्रशासन जरूरी है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए उचित नियमों का पालन होना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया भी महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है। समाज को ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिसमें पीड़ित महिला को दोष देने के बजाय अपराधी के खिलाफ आवाज उठाई जाए। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण ही सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकता है।

महिला सुरक्षा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज का विषय है। जब तक समाज का हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक पूरी तरह सुरक्षित वातावरण बनाना कठिन होगा। पुरुषों की भागीदारी भी इस दिशा में बेहद जरूरी है। पुरुषों को महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक होना होगा तथा समानता की भावना को मजबूत करना होगा।

-शिवांश धाकड़

पवित्र रावी नदी की पुकार

कविता

मनीश चोणा, मनु, मोहल्ला
सपड़ी, चंबा शहर

सायं सायं कियां करां बजिया, के तुसां मिंजों घोटी सुटेया!
मुकि गेई चाल मेरी, छडी गे नखरे, गोडे-गोडे पानी रेहा,
बट्टे लिबण बखरे। अपणा रुप करकोणा दिखी कौफ मिंजों लगदा!
ते मिंजों बड़ा दु:ख लगदा। कियां चंबे दे लौकां करने हसणा ते
बोलणा मैं! चमेरे वालेयां ने पता नी, गेट खोलणा कि नी खोलना!
तुसां कने नी मिली पांदी, ता कौफ मिंजो लगदा , ते मिंजों बड़ा
बुरा लगदा! भ्यागा, दिहाड़ी ता मैं सुकी-मुकी जांदी, बेटैमी बरखा बिच
मैं सब कुछ रुढांदी! मेरे कंडे/किनारे बसने का अबे हर कोई डरदा!
ते मिंजों बड़ा कौफ लगदा! सायं सायं कियां करां बजिया,
लोकां ने मिंजों घोटी छड़ेया!

पंचायत से लेकर केंद्र तक साझेदारी का मॉडल बनेगा खेत बचाओ अभियान

प्रवीण कुमार
स्वतंत्र लेखक

भारतीय कृषि व्यवस्था में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार खेती है। ऐसे में किसानों को सही समय पर सही जानकारी, वैज्ञानिक सलाह और आधुनिक तकनीकों से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया खेत बचाओ अभियान केवल एक जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि खेत, किसान और गांव को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय प्रयास है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को संतुलित और विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करना है। लगातार बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। अभियान के माध्यम से किसानों को मिट्टी परीक्षण आधारित खेती, उचित मात्रा में खाद का प्रयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेत बचाओ अभियान को प्रभावी और परिणामकारी बनाया जाए। इसका ध्यान केवल संदेश देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि किसानों को खेत स्तर पर व्यावहारिक सलाह उपलब्ध करानी होगी। बदलते मौसम और कृषि संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर मार्गदर्शन देना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कृषि विशेषज्ञ किसानों को बताएंगे कि कौन सी फसल किस मौसम में बेहतर रहेगी और कम पानी या जोखिम वाली परिस्थितियों में कौन से विकल्प अपनाए जा सकते हैं।

किसानों को हरी खाद, जैविक खाद और जैव उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। इससे लंबे समय तक खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य है कि अभियान केवल सरकारी विभागों तक सीमित न रहे बल्कि गांव के किसान, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय संस्थाएं भी इसमें शामिल हों।

पंचायत स्तर पर किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधे खेत तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दलहन और तिलहन मिशन, जल संरक्षण और क्षेत्र विशेष कृषि योजनाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

आज कृषि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बदलता मौसम है। अनियमित बारिश, तापमान में बदलाव और जल संकट किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में किसानों को फसल चयन, खेती की तकनीक और जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी देना जरूरी है।

अभियान के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि मौसम के अनुसार कौन सी फसलें लाभकारी हो सकती हैं। इसके अलावा कम पानी वाली खेती और फसल विविधीकरण जैसे विकल्पों पर भी जोर दिया जाएगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी ने जगाई स्वतंत्रता की नई चेतना

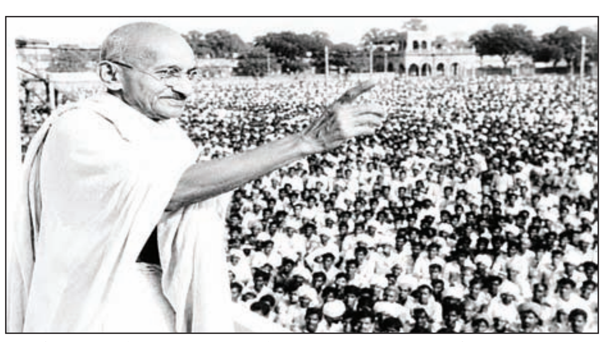

दिनेश दमाथीआ
स्वतंत्र लेखक

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1920 एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसी वर्ष महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। यह पहला ऐसा व्यापक जन आंदोलन था जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी और करोड़ों भारतीयों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया। 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इस दिन गांधी जी ने देशवासियों से अपील की कि वे ब्रिटिश शासन के साथ हर प्रकार का सहयोग समाप्त कर दें और अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आगे आएं। संयोगवश इसी दिन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ था। गांधी जी ने तिलक को श्रद्धांजलि देते हुए देशवासियों से उनके अधूरे स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश सरकार की हर संभव सहायता की थी। लाखों भारतीय सैनिक युद्ध में शामिल हुए और जनता ने आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया। भारतीयों को आशा थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें अधिक राजनीतिक अधिकार और स्वशासन प्रदान करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और नजरबंदी जैसी कठोर व्यवस्थाएं लागू की गईं। इस कानून ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया।

इसी वर्ष 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दीं। इस भीषण नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने भारतीयों का ब्रिटिश शासन पर बचा-खुचा विश्वास भी समाप्त कर दिया। गांधी जी ने महसूस किया कि अन्यायपूर्ण शासन के साथ सहयोग करना नैतिक रूप से गलत है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर एक ऐसे आंदोलन की योजना बनाई जिसमें हिंसा का सहारा लिए बिना अंग्रेजी शासन को कमजोर किया जा सके।

इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति कमजोर होने से भारतीय मुसलमानों में असंतोष था। गांधी जी ने हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से खिलाफत नेताओं का समर्थन किया और दोनों आंदोलनों को एक साथ जोड़ दिया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला और देश के विभिन्न समुदाय एक मंच पर आए।

सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इसके बाद पूरे देश में आंदोलन तेज गति से फैल गया। गांधी जी ने लोगों से सरकारी उपाधियां लौटाने, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार करने, सरकारी अदालतों का उपयोग न करने, विदेशी वस्तुओं का त्याग करने, विदेशी कपड़ों की होली जलाने तथा सरकारी समारोहों से दूर रहने की अपील की।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

धूम्रपान से दूरी और समय पर उपचार ही फेफड़ों के कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय

डॉ. सत्यवान सौरभ
सामाजिक विचारक

हर वर्ष 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करना और इस गंभीर बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में शामिल है। यह बीमारी केवल धूम्रपान करने वालों तक सीमित नहीं है बल्कि धूम्रपान न करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए इस रोग के कारणों लक्षणों बचाव और उपचार के बारे में सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

फेफड़े हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं जो सांस लेने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। जब फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और उनमें असामान्य परिवर्तन होने लगता है तब कैंसर विकसित हो सकता है। शुरुआत में यह रोग अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ता रहता है। यही कारण है कि अधिकांश मामलों में इसका पता तब चलता है जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। यदि प्रारंभिक अवस्था में इसकी पहचान हो जाए तो उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है।

फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू का सेवन माना जाता है। बीड़ी सिगरेट हुक्का और अन्य तंबाकू उत्पादों का लंबे समय तक उपयोग करने से इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा परोक्ष धूम्रपान यानी किसी दूसरे व्यक्ति के धूम्रपान के धुएं के संपर्क में रहना भी जोखिम बढ़ाता है। वायु प्रदूषण औद्योगिक रसायनों के संपर्क में लंबे समय तक रहना एस्बेस्टस जैसी हानिकारक सामग्री के संपर्क में आना तथा कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण भी इस रोग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। लगातार खांसी बने रहना खांसी के साथ खून आना सांस लेने में तकलीफ सीने में दर्द आवाज बैठ जाना बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना बार बार फेफड़ों का संक्रमण होना अत्यधिक थकान महसूस होना और भूख कम लगना इसके प्रमुख संकेत हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना रहे तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। समय पर जांच जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

फेफड़ों के कैंसर की पहचान के लिए कई आधुनिक जांच उपलब्ध हैं। चिकित्सक रोगी की स्थिति के अनुसार एक्स रे सीटी स्कैन बायोप्सी ब्रोंकोस्कोपी और अन्य परीक्षण कराने की सलाह देते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से धूम्रपान की आदत है या जो उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। प्रारंभिक जांच से रोग को शुरुआती चरण में पकड़ना संभव हो सकता है जिससे उपचार अधिक प्रभावी हो जाता है।

उपचार के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले जहां इस बीमारी का उपचार सीमित विकल्पों तक था वहीं अब आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों ने मरीजों के लिए नई उम्मीदें पैदा की हैं। उपचार रोग की अवस्था और मरीज की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। इसमें शल्य चिकित्सा विकिरण चिकित्सा कीमोथेरेपी लक्षित उपचार और प्रतिरक्षा चिकित्सा जैसी विधियां शामिल हो सकती हैं। आज कई मरीज समय पर उपचार के कारण लंबे समय तक सामान्य जीवन जी रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

ओम प्रकाश धनखड़ का राजनीतिक सफर

ओम प्रकाश धनखड़
जन्म : 1 अगस्त 1961

ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय राजनीति के एक अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका जन्म **1 अगस्त 1961** को हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक अनुभव तथा सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं।

ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से की। छात्र जीवन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा के प्रति रुचि दिखाई देने लगी थी। उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर अपनी पहचान बनाई।

धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता आधार को मजबूत करने, संगठन को विस्तार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए काम किया। उनकी कार्यशैली में संगठन प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद प्रमुख विशेषता माना जाता है।

हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश धनखड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर उनका विशेष ध्यान रहा है। किसान हितों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी भूमिका प्रस्तुत की।

राजनीति में ओम प्रकाश धनखड़ की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो संगठन और जनसंपर्क को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे लगातार जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि मजबूत संगठन और जनता से जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए आवश्यक है। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण धनखड़ को हरियाणा भाजपा के प्रमुख रणनीतिक नेताओं में गिना जाता है।

‘भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

बस्ती में 23 करोड़ की एफडीए बिल्डिंग में दरारें, भाजपा नेता ने उठाए सवाल

एजेंसी, बस्ती। बस्ती जिले में 23 करोड़ रुपये की लागत से बने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अत्याधुनिक भवन में सात महीने बाद ही दरारें आने का मामला सामने आया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अजय पाल सिंह ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता की जांच और कार्रवाई की मांग की है। जिला मुख्यालय से करीब सात किलोमीटर दूर बने इस भवन की दीवारों में दरारों के साथ परिसर की आरसीसी सड़क भी कई जगह टूट गई है। भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश सिडक ने वर्ष 2025 में पूरा किया था और जनवरी 2026 में इसे विभाग को सौंपा गया था। जूनियर इंजीनियर ने दरारों को एयर क्रेक बताते हुए मरम्मत कराने की बात कही है।

गोरखपुर बालिका हत्याकांडः आरोपी सिपाही की बहाली पर उठे सवाल

एजेंसी, गोरखपुर। बालिका हत्याकांड के आरोपी बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव की दोबारा तैनाती को लेकर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। डायल 112 में तैनात रहे अभिषेक यादव पर पहले भी एक युवती से गंभीर दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके थे। गोरखनाथ थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे जेल भेजा गया था। अब सवाल उठ रहा है कि गंभीर आरोपों और कार्रवाई के बावजूद उसे फिर उसी जिले में ड्यूटी कैसे मिल गई। बताया जा रहा है कि निलंबन के 90 दिन बाद उसकी बहाली हुई थी। आरोपी सिपाही की तैनाती प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। मामले में आगे जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है।

बिजनौर प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में सात दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

एजेंसी, बिजनौर। बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो के न्यायाधीश शहजाद अली ने सभी दोषियों पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2012 में हुए इस हत्याकांड में संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल उर्फ शैलू, निखिल अग्रवाल और अनुज गुप्ता को दोषी ठहराया गया था। दोषियों में कई रसूखदार और बड़े व्यापारी शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल के पति और बेटे का नाम भी शामिल है। कोर्ट ने जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। साथ ही विवेचना में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

गंगा-घाघरा समेत दस नदियां उफान पर 24 शहरों में बारिश अलर्ट

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर प्रदेश की नदियों पर दिखाई दे रहा है। गंगा, घाघरा-सरयू समेत करीब 10 नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में गुरुवार शाम शारदा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार नौ लोग नदी में बह गए,

जिनमें से सात लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि दो लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन और बचाव दल राहत अभियान में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैयारियां तेज कर दी हैं। राहत और बचाव टीमों को अलर्ट पर रखा गया है तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का बढ़ेगा दायरा, अधिक से अधिक छात्रों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक

एजेंसी, लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी बच्चों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसान कल्याण, कृषि विपणन व्यवस्था, मंडियों के आधुनिकीकरण और विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 3025.49 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए।

उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए मंडी स्थलों पर पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने मंडी परिसरों में कृषि उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के माध्यम से ऐसी इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें।

उन्होंने इसके लिए नियमों को सरल और निवेश के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक मंडियों को ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और प्रत्येक जिले में जैविक उत्पादों के प्रमाणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि व्यवस्था से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित आय-व्यय अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट को स्वीकृति दी गई। बजट में 2228.59 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों और 3025.49 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है। मंडी स्थलों के निर्माण, विस्तार, संपर्क मार्गों की मरम्मत, ग्रामीण हाट, किसान बाजार, गोवंश आश्रय स्थल, छात्रावास निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की मंडी समितियों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में मंडी समितियों की आय 1991.33 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2305.80 करोड़ रुपये पहुंच गई।

भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने उधम सिंह और प्रेमचंद को किया नमन

एजेंसी, वाराणसी

भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने शुक्रवार को अपने खोजवा स्थित आवास पर अमर शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस और महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने दोनों महान विभूतियों के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अशोक चौरसिया ने कहा कि शहीद उधम सिंह अदम्य साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे।

अशोक चौरसिया ने महान विभूतियों को किया याद

जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए भारतीयों के बलिदान को उन्होंने कभी नहीं भुलाया और लंदन जाकर जनरल डायर के सहयोगी माइकल ओ डायर को मारकर देशवासियों के साथ हुए अत्याचार का बदला लिया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने गदर पार्टी के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों में भी स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले उधम सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका त्याग और संघर्ष राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल है। वहीं, मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए अशोक चौरसिया ने कहा कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान स्तंभ थे। उनकी रचनाओं में समाज की वास्तविक तस्वीर, गरीबों की पीड़ा, सामाजिक विषमताओं और शोषण के खिलाफ आवाज देखने को मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहा है। उनकी कहानियां और उपन्यास मानव संवेदनाओं का सशक्त चित्रण करते हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों और साहित्यकारों के आदर्शों को अपनाकर समाज और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। उधम सिंह का बलिदान और प्रेमचंद का साहित्य सदैव लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।

कानपुर किडनी कांड में डॉक्टर दंपती समेत चार आरोपियों को मिली जमानत

एजेंसी, कानपुर

कानपुर के चर्चित किडनी कांड में आरोपी डॉक्टर दंपती समेत चार लोगों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। आहूजा अस्पताल के डॉक्टर दंपती डॉ. प्रीति आहूजा और डॉ. सुरजीत को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि अन्य दो अस्पताल संचालकों राजेश कुमार और नरेंद्र सिंह को जिला जज कोर्ट ने राहत दी है।

आहूजा अस्पताल बिहार के मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर को छात्र आयुष कुमार की किडनी लगाई गई थी

चारों आरोपी करीब चार महीने से जेल में बंद थे। पुलिस ने 30 मार्च को आहूजा अस्पताल में कथित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का खुलासा किया था। जांच के दौरान आरोप लगाया गया था कि बिहार की रहने वाली पारुल तोमर को छात्र आयुष कुमार की किडनी प्रत्यारोपित की गई थी। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने अस्पताल से जुड़े कई लोगों को आरोपी बनाया था।

बनारस की कराटे खिलाड़ी गौरी पाठक वर्ल्ड पुलिस गेम्स में चयनित

एजेंसी, वाराणसी। लहरतारा निवासी कराटे खिलाड़ी गौरी पाठक ने अपनी प्रतिभा के दम पर एक और उपलब्धि हासिल की है। गौरी का चयन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए हुआ है। हाल ही में उन्होंने 11वें ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर-2026 में व्यक्तिगत कुमिते (-61 किलोग्राम) स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। जिला कराटे संघ के महासचिव दिलीप कुमार सैनी और कोच किसलय मानव ने बताया कि गौरी ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित 9वीं साउथ एशियन कराटे प्रतियोगिता में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक हासिल किया था। प्रतियोगिता का आयोजन 5 और 6 जुलाई को हुआ था। गौरी पाठक वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वह मानव अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से सेकेंड डिग्री ब्लैक बेल्ट प्राप्त खिलाड़ी हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा : जिलाधिकारी

एजेंसी, वाराणसी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने तहसील सदर स्थित निर्वाचन कार्यालय के ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक बाह्य निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या, उनकी कार्यशीलता, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, खिड़कियों और रोशनदानों की सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

जिलाधिकारी ने बाहरी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए आयोग के सभी मानकों का शत-प्रतिशत पालन करने को कहा। उन्होंने सुरक्षा गार्डों की शिफ्टवार तैनाती, प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था और वेयरहाउस की समग्र सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया।

लबकनी गांव में आंबेडकर प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पांच कर्मचारी निलंबित

एजेंसी, देवरिया

गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लबकनी गांव में सरकारी खलिहान की भूमि पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुए विवाद के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर पुलिस और राजस्व विभाग के पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के अनुसार, बुधवार शाम दलित समुदाय के कुछ लोगों ने सरकारी खलिहान की भूमि पर चबूतरा बनाकर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा रख दी थी। गुरुवार सुबह इसे लेकर गांव में विवाद शुरू हो गया। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि सार्वजनिक सरकारी भूमि पर प्रशासन की अनुमति के बिना प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। उन्होंने प्रतिमा को आबादी क्षेत्र या किसी पार्क में नियमानुसार अनुमति लेकर स्थापित करने का सुझाव दिया था।

विवाद की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ अराजकतत्वों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए।

घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा की। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही मिलने पर गौरी बाजार थाने के उपनिरीक्षक अरविंद कुमार यादव, बीट हेड कांस्टेबल रमेश यादव, एलआईयू बीट हेड कांस्टेबल नागेंद्र सिंह, संबंधित लेखपाल और पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है।

प्रेमचन्द की रचनाएं आज भी देती हैं समाज को नई सोच : नेहा गुप्ता

एजेंसी, प्रयागराज

कथासम्राट मुंशी प्रेमचन्द की जयंती के अवसर पर 'सर्जनपीठ', प्रयागराज के तत्वावधान में 'प्रेमचन्द कथा लेखन की प्रासंगिकता' विषय पर राष्ट्रीय ऑनलाइन बौद्धिक परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों और विद्वानों ने प्रेमचन्द के साहित्य और सामाजिक योगदान पर अपने विचार रखे।

मुंशी प्रेमचन्द का साहित्य सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का सशक्त माध्यम

मुख्य वक्ता आकाशवाणी प्रयागराज की कार्यक्रम प्रमुख एवं सहायक निदेशक (कार्यक्रम) नेहा गुप्ता ने कहा कि प्रेमचन्द की यथार्थवादी लेखनी ने सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों और विषमताओं पर प्रभावी प्रहार किया। उनकी रचनाएं आज भी समाज को नई सोच और सही दिशा प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि 'गोदान', 'गबन', 'कफन' और 'सेवासदन' जैसी कृतियां प्रेमचन्द की गहरी सामाजिक समझ को दर्शाती हैं। कार्यक्रम के आयोजक एवं भाषाविद् आचार्य पं. पृथ्वीनाथ पाण्डेय ने कहा कि प्रेमचन्द का साहित्य समाज का सजीव दर्पण है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक अन्याय, असमानता और मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी।

परिसंवाद में देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने प्रेमचन्द के साहित्य में मानवता, समानता और नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचन्द का कथा-साहित्य वर्तमान समय में भी समाज के लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक बना हुआ है।

सावन मास के दूसरे दिन भी काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

एजेंसी, वाराणसी। श्रावण मास के दूसरे दिन काशी में शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगा स्नान के बाद पवित्र जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक कांवड़ियों के जत्थे हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ आगे बढ़ते नजर आए। पूरे मार्ग और धाम परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में रेड कार्पेट बिछाया गया है, जिससे आवागमन सुगम हो सके।

श्रावण मास में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, एंबुलेंस, विश्राम स्थल और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रवेश और निकास द्वारों पर विशेष व्यवस्था की गई है। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से धाम परिसर की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। देश-विदेश से आए श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इसके आगे श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की है। धाम परिसर में खोया-पाया केंद्र और सूचना केंद्र श्रद्धालुओं की सहायता के लिए लगातार सक्रिय हैं।

पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी घायल, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

एजेंसी, बागपत

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में थाना दोघट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस समेत एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, 28 जुलाई को थाना दोघट क्षेत्र के गांव फोलादनगर में प्रतिबंधित पशु कटान की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की थी, जहां से पशु अवशेष बरामद हुए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। फरार चल रहे एक आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गुरुवार देर रात मुखबिर से मिली सूचना के बाद दोघट पुलिस ग्राम मिलाना के जंगल क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राशिद पुत्र इमरान निवासी फोलादनगर के रूप में हुई है।

पुलिस ने उसके पास से .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि आरोपी गौकशी मामले में वांछित था और उसके अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मामले में पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

चुनौती — 264 मरीजों पर शोध में सामने आया टीबी और मधुमेह का गंभीर संबंध

मधुमेह वाले एमडीआर टीबी मरीजों में मौत का खतरा ज्यादा

एजेंसी, गाजीपुर

बहु दवा प्रतिरोधी (एमडीआर) टीबी से पीड़ित मरीजों के इलाज को लेकर नई चुनौती सामने आई है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के एक अध्ययन में सामने आया है कि एमडीआर टीबी के साथ टाइप-2 मधुमेह से पीड़ित मरीजों में टीबी की दवाओं का असर धीमा होता है। ऐसे मरीजों में संक्रमण खत्म होने में अधिक समय लगता है और लंबे इलाज के कारण गंभीर जटिलताओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

केजीएमयू के श्वसन रोग विभाग की ओर से वर्ष 2023 से 2024 के बीच किए गए अध्ययन में 264 एमडीआर टीबी मरीजों को शामिल किया गया। इनमें 155 पुरुष और 109 महिलाएं थीं। मरीजों को तीन समूहों में बांटा गया। पहले समूह में 61 टाइप-2 मधुमेह से पीड़ित मरीज, दूसरे समूह में 66 प्री-डायबिटीज यानी मधुमेह की शुरुआती स्थिति वाले मरीज और तीसरे समूह में 137 ऐसे मरीज शामिल थे, जिन्हें मधुमेह नहीं था। सभी मरीजों को मुंह से ली जाने वाली टीबी की दवाएं दी गईं और इलाज के दौरान नियमित रूप से उनकी बलगम जांच, स्वास्थ्य स्थिति और संक्रमण में सुधार की निगरानी की गई।

प्रो. सूर्यकांत

डॉ. ज्योति बाजपेयी

अध्ययन में पाया गया कि मधुमेह से पीड़ित मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण की गंभीरता अधिक थी और टीबी के जीवाणुओं की संख्या भी ज्यादा पाई गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि मधुमेह मरीजों में टीबी के जीवाणुओं में दवा प्रतिरोध बढ़ाने वाले आईएनएचए और केएटीजी जीन में बदलाव यानी म्यूटेशन मिले।

इलाज के दौरान बलगम जांच सामान्य होने में मधुमेह मरीजों को औसतन 133 दिन लगे। वहीं प्री-डायबिटीज मरीजों में यह समय 113 दिन और बिना मधुमेह वाले मरीजों में 97 दिन रहा। केजीएमयू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के संस्थापक प्रभारी प्रो. सूर्यकांत ने बताया कि भारत में टीबी और मधुमेह दोनों ही बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां हैं। एमडीआर टीबी मरीजों में मधुमेह एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक बन सकता है। इसलिए प्रत्येक एमडीआर टीबी मरीज की मधुमेह और प्री-डायबिटीज की जांच कराना जरूरी है। दोनों बीमारियों का एक साथ इलाज और लगातार निगरानी करने से मरीजों के बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं।

एमडीआर टीबी के प्रमुख कारण

- टीबी का अधूरा इलाज छोड़ देना
- दवाओं का अनियमित या गलत सेवन
- एमडीआर टीबी मरीज से संक्रमण फैलना
- टीबी जीवाणुओं में आनुवंशिक बदलाव
- शरीर की कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता

क्या है एमडीआर टीबी

एमडीआर टीबी यानी मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस सामान्य टीबी से अधिक गंभीर होती है। इसमें टीबी के जीवाणु प्रमुख दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे इलाज कठिन और लंबा हो जाता है। मरीज को कई महीनों तक दवाएं लेनी पड़ती हैं और लापरवाही करने पर संक्रमण बढ़ सकता है।

पूर्व भाजपा विधायक की बेटी यशस्वी राजे ने शिक्षा मंत्री फैसले पर उठाए सवाल

एजेंसी, फतेहपुर

भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे ने केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हालिया बदलावों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नियुक्ति और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई टिप्पणियां कीं।

शिक्षा मंत्री नियुक्ति को लेकर यशस्वी राजे की टिप्पणी

शिक्षा मंत्रालय बदलाव को लेकर सामने आई नई प्रतिक्रिया

यशस्वी राजे ने कतर के एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, उसमें उन्हें बलिदानी दिखाने की कोशिश नजर आती है। उन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति के फैसले को निराशाजनक बताया और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में होने वाले बदलावों को लेकर व्यापक सोच और चर्चा की जरूरत होती है। यशस्वी राजे की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

हालांकि, उनके पिता और भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी राजे के बयान उनके व्यक्तिगत विचार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटी ने जो भी टिप्पणी की है, वह उनकी निजी राय है और इसका पार्टी या परिवार की राजनीतिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय में बदलाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार की ओर से किए गए फैसलों को लेकर जहां समर्थक इसे प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर कर रहे हैं।

यशस्वी राजे की टिप्पणी ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। उनके बयान के बाद भाजपा और विपक्षी दलों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिक्षा मंत्रालय में हुए बदलावों को लेकर जहां सरकार समर्थक इसे प्रशासनिक निर्णय बता रहे हैं, वहीं विपक्ष और कुछ अन्य लोग इससे जुड़े सवाल उठा रहे हैं।

657 करोड़ घोटाले में आईएएस पंकज अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, सीबीआई ने जमानत पर जताई आपत्ति

सीबीआई ने विशेष अदालत में कहा कि आईएएस पंकज अग्रवाल घोटाले के कथित मास्टरमाइंड के करीबी थे

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

हरियाणा के चर्चित 657 करोड़ रुपये के कथित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जमानत का कड़ा विरोध किया।

जांच एजेंसी ने अदालत में दायर अपने जवाब में कहा कि पंकज अग्रवाल मामले के कथित मास्टरमाइंड और चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व अधिकारी रिभव ऋषि के करीबी सहयोगी थे तथा उन्हें आर्थिक और अन्य अनुचित लाभ प्राप्त हुए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पंकज अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2024 से 16 जून 2025 तक हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया।

आईएएस पंकज अग्रवाल की जमानत पर फैसला तीन अगस्त को।

इसी दौरान 17 दिसंबर 2024 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से भेजे गए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) का बैंक खाता खोलने के प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी। जांच एजेंसी का आरोप है कि यह मंजूरी निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के विपरीत दी गई, जिसके बाद करोड़ों रुपये के सरकारी धन के लेनदेन का रास्ता खुला। सीबीआई का कहना है कि इस पूरे मामले में बैंकिंग नियमों और सरकारी वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई। एजेंसी के अनुसार, खाते के संचालन और धन के हस्तांतरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। जांच अधिकारियों ने अदालत में यह भी कहा कि मामले में कई अहम दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय लेनदेन की कड़ियां अभी जांच के दायरे में हैं।

ऐसे में आरोपी को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित होने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी दलील दी कि पंकज अग्रवाल की भूमिका केवल प्रशासनिक मंजूरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर उनकी संलिप्तता की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि मामले की गंभीरता, सरकारी धन की बड़ी राशि और जांच की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरोपी को नियमित जमानत न दी जाए।

छह महीने तक मासूम पर अत्याचार सौतेली मां सहित बेटा आरोपी

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

हरियाणा के पानीपत जिले से एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर छह महीने तक लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना किए जाने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार, बच्ची की सौतेली मां उस पर अत्याचार करती थी और उसे कई बार नग्न अवस्था में कमरे में बंद रखा जाता था। मामले में सौतेले भाई पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया है।

परिजनों की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद जांच शुरू की गई। आरोप है कि बच्ची लंबे समय से प्रताड़ना झेल रही थी, लेकिन भय और दबाव के कारण वह किसी को कुछ बता नहीं सकी। मामले की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आए। घटना की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही आरोप है कि आयोग की चेयरपर्सन द्वारा संपर्क किए जाने के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों से समय पर बात नहीं हो सकी, जिस पर भी सवाल उठे हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित आरोपितों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।आयोग ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही बच्ची की सुरक्षा, उचित चिकित्सकीय देखभाल और मनोवैज्ञानिक परामर्श सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

न्यूज ब्रीफ

कैथल में चिट्टा तस्करों से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। हरियाणा के कैथल जिले में एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने पर टीम ने संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। मौके से चार आरोपियों को पकड़ लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी संदीप फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 48.43 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की। देर रात पूंडरी-फरल नहर के पास पुलिस और संदीप का आमना-सामना हुआ। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी, पुलिस पर हमला और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है।

रेवाड़ी जेल में हवालातियों के दो गुट भिड़े, एक दर्जन घायल, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिला जेल में हवालातियों के दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में करीब एक दर्जन बंदी घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद जेल का गेट खोलने को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना के बाद जेल प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति पर काबू पाया तथा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मामले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि झड़प के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषी बंदियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।

मां बनने के बाद सीमा का शानदार कमबैक कॉमनवेल्थ में जीता कांस्य पदक

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली डिस्कस थ्रोअर सीमा कालीरमन ने मां बनने के बाद शानदार वापसी करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने चार वर्षीय बेटे रुद्र को दिया है। उनका कहना है कि बेटे की छोटी-छोटी बातें उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। सीमा ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान जब वह अभ्यास करती थीं तो उनका बेटा रुद्र उन्हें देखकर कहता था, 'मां वेरी गुड '। बेटे की यह आवाज उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गई। मां बनने के बाद खेल में वापसी करना आसान नहीं था, लेकिन परिवार के सहयोग और अपने आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी। सीमा ने कहा कि खिलाड़ी के जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति समर्पण और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी फिटनेस पर दोबारा काम किया और लंबे अभ्यास के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की।

जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी जांच में नहीं मिला कोई सुराग

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। फतेहाबाद जिला न्यायिक परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला सेशन कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल भेजा गया, जिसमें 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिखे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली करवाकर सुरक्षा बढ़ा दी। एसपी निकिता खट्टर मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कराई। हिसार से डॉग स्क्वॉयड और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर पूरे परिसर की जांच की गई। साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी है। पुलिस ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है।

सोनीपत में मां ने दो साल के बेटे की पानी में डुबोकर हत्या, गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत

हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र के मुंडलाना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला पर अपने ही दो वर्षीय बेटे चिराग को पानी की होदी में डुबोकर हत्या करने का आरोप है। शुरुआती तौर पर बच्चे की मौत को हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच और पति की शिकायत के बाद मामला हत्या का निकला।

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला प्रिया को शक था कि उसके पति के किसी दूसरी महिला से संबंध हैं। उसे यह भी डर था कि पति उसे छोड़कर बच्चों को अपने पास रख लेगा। इसी आशंका और पारिवारिक विवाद के चलते उसने कथित रूप से अपने मासूम बेटे की जान ले ली। घटना के बाद परिवार ने पहले इसे दुर्घटना माना, लेकिन

पति पर शक में मासूम बेटे की हत्या, मां गिरफ्तार

महिला के व्यवहार और परिस्थितियों पर संदेह होने पर पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं : कृष्णपाल गुर्जर

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव और नगर निगम के एक्सईएन डालचंद शर्मा के बीच चल रहे विवाद पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पार्षद को समस्या थी तो वह विधायक, नगर निगम कमिश्नर, मंत्री या मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख सकते थे। मामला 28 जुलाई का है, जब पार्षद दीपक यादव ने बल्लभगढ़ नगर निगम जोन कार्यालय में पहुंचकर एक्सईएन के कार्यालय के बाहर जंजीर और ताला लगा दिया था। उनका आरोप था कि वार्ड-43 में सीवर लाइन का काम स्वीकृत होने के बाद भी शुरू नहीं किया गया। वहीं, कर्मचारियों ने अधिकारी से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया है।

फतेहाबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वॉड पहुंची, पुलिस ने परिसर खाली कराया

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

हरियाणा के फतेहाबाद स्थित न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सेशन कोर्ट की आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया और मुख्य प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

धमकी की सूचना मिलते ही हिसार से डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। सुरक्षा टीमों ने न्यायालय परिसर के सभी भवनों, कोर्ट कक्षों, कार्यालयों, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के परिसर की गहन तलाशी शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरे क्षेत्र

की बारीकी से जांच की जा रही है और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा।

तलाशी अभियान के दौरान न्यायालय परिसर में आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। वकीलों, कर्मचारियों और न्यायालय में आए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसर खाली कराया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लेकर जांच प्रक्रिया जारी रखी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरे ईमेल की सत्यता और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है।

ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और उसके उद्देश्य का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

हरियाणा में नकली दवाओं का कारोबार बेनकाब, करोड़ों के नेटवर्क पर कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। विशेष अभियान के तहत अब तक 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 12 गिरफ्तारियां गुरुग्राम से हुई हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 70 लाख रुपये मूल्य की नकली दवाएं और 323 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं बरामद की गई हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एफडीए ने राज्यभर में खुफिया सूचनाओं के आधार पर निगरानी, छापेमारी और सैंपलिंग अभियान तेज किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के निर्देश पर यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। राज्य औषधि नियंत्रक रिपन मेहता ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा एफडीए की कार्रवाई में 70 लाख रुपये की नकली दवाएं जब्त, 16 आरोपी गिरफ्तार।

जांच के दौरान गुरुग्राम में नकली दवाओं के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ। अप्रैल 2026 में एफडीए ने डीएलएफ फेज-4 और सेक्टर-69 में छापेमारी कर नकली मौनजारो इंजेक्शन रैकेट का पर्दाफाश किया था। वहां से करीब 70 लाख रुपये मूल्य के नकली इंजेक्शन जब्त किए गए थे। इसके बाद जुलाई में नकली टेल्मा-एएम गोलियों के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। जांच के दौरान तोफाजैक 5 एमजी समेत कई अन्य संदिग्ध दवाएं भी सामने आईं। हरियाणा और दिल्ली एफडीए की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली के एक अवैध परिसर से नकली एनाबालिक स्टेरॉयड सहित 323 प्रकार की दवाएं तथा 23 हजार आर-जारा डीएसआर कैप्सूल भी जब्त किए गए।

एफडीए का कहना है कि नकली दवाओं के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने लोगों से केवल अधिकृत मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने और किसी भी संदिग्ध दवा या अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया कि नकली दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आम लोगों से अपील की गई है कि दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें और संदिग्ध उत्पाद मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।

फतेहाबाद में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को तैनात होंगे पुलिस के 500 जवान

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए फतेहाबाद पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। हरिद्वार से आने वाले हजारों शिवभक्तों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी।

एसपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना, संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र लागू किया गया है। जिले में करीब 500 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों, पीसीआर, ईआरवी और पुलिस राइडर टीमों को अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों के आवागमन को देखते हुए जिले के प्रमुख मार्गों पर विशेष सुरक्षा

व्यवस्था की गई है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-09, हिसार सीमा से फतेहाबाद सीमा तक, स्टेट हाईवे-02 सनियाना-भूना-फतेहाबाद मार्ग, एनएच-148बी नरवाना-टोहाना-कुलां-रतिया-हांसपुर मार्ग सहित अन्य प्रमुख रास्ते शामिल हैं। इन मार्गों पर मोबाइल पुलिस टीमें दिन-रात निगरानी रखेंगी।

यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी के लिए डीएसपी यातायात जयसिंह को जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। थाना यातायात प्रबंधक को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस ने कांवड़ियों के ठहरने और भोजन के लिए बनाए जा रहे शिविरों की नियमित जांच के निर्देश भी दिए हैं। जरूरत पड़ने पर शिविरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

राज्यसभा में गुरुग्राम में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने की मांग उठी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद संजय भाटिया ने गुरुग्राम में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह केवल न्यायिक सुविधा का विषय नहीं, बल्कि न्याय तक आसान पहुंच, न्यायिक विकेंद्रीकरण और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने से जुड़ा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है।

सदन में अपनी बात रखते हुए संजय भाटिया ने कहा कि वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट केवल चंडीगढ़ में स्थित है। इसके कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दक्षिण हरियाणा के अन्य जिलों के लाखों वादकारियों, अधिवक्ताओं, उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा कॉरपोरेट संस्थानों को हर मामले के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है। इससे मुकदमेबाजी का खर्च बढ़ता है, यात्रा में अधिक समय लगता है और समय पर न्याय मिलने में कठिनाई आती है। उन्होंने

दक्षिण हरियाणा को हाईकोर्ट सर्किट बेंच की मांग मिली गति

कहा कि गुरुग्राम आज देश का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी, कॉरपोरेट, वित्तीय सेवाओं और स्टार्टअप गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका है।

यहां वाणिज्यिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, मध्यस्थता, कर विवाद, दिवालियापन और संवैधानिक मामलों से जुड़े बड़ी संख्या में प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे में गुरुग्राम में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना समय की आवश्यकता है। संजय भाटिया ने यह भी कहा कि हाल ही में गुरुग्राम में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, जहां आधुनिक न्यायिक अवसंरचना, डिजिटल कोर्टरूम और ई-कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके अनुसार, यह परिसर हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के संचालन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि गुरुग्राम में सर्किट बेंच बनने से दक्षिण हरियाणा के लोगों को न्याय सुलभ होगा, लंबित मामलों का बोझ कम होगा और न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर्किट बेंच की स्थापना से अधिवक्ताओं, उद्योगों और आम नागरिकों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ, तेज और किफायती बनेगी। सांसद ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस प्रस्ताव पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर दक्षिण हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत देने की अपील की।

सुनैना चौटाला ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बोलीं- जनता देगी करारा जवाब

सुनैना चौटाला का दावा- प्रदेश में बदलाव के लिए जनता तैयार, जंतर-मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई को बताया गलत, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

इनेलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने शुक्रवार को फतेहाबाद हलके के ग्रामीण दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है। महिला, युवा, किसान, छात्र और व्यापारी सभी अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब सरकार की नीतियों का जवाब देने के लिए तैयार है।

सरवरपुर गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि जंतर-मंतर पर अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर कार्रवाई करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करेगी।

सुनैना चौटाला ने कहा कि सरकार का मुख्य दायित्व लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन हरियाणा में इन क्षेत्रों में अपेक्षित

काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान फतेहाबाद जिले की अनदेखी की गई। जिले में नए स्कूल और कॉलेज नहीं खोले गए।

उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाकर लोगों से वोट लिए गए, लेकिन अब इसे टोहाना स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है, जो क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा। सुनैना चौटाला ने कहा कि किसान खराब फसलों के मुआवजे और अपनी उपज के उचित दाम के लिए परेशान हैं। उन्हें अपनी मांगों के लिए बार-बार सरकार के सामने आवाज उठानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। इनेलो नेता ने ग्रामीणों से पार्टी को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है।

उन्होंने बताया कि पूर्व उपप्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती के अवसर पर 27 सितंबर को नूंह में राज्य स्तरीय सम्मान दिवस रैली आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 10 अगस्त को फतेहाबाद के सिरसा रोड स्थित सेतिया पैलेस में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सुनैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से दोनों कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में

फतेहाबाद ग्रामीण दौरे में इनेलो ने दिखाई राजनीतिक सक्रियता

पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इनेलो जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और भविष्य में भी लोगों की आवाज उठाती रहेगी।

ग्रामीण दौरे के दौरान इनेलो जिला प्रधान बीकर सिंह हड़ौली, हलका प्रधान अंगद ढिंगसरा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें भागीराम सोनी, रामस्वरूप दुग्गल, डॉ. नफे सिंह जाखड़, अजय मांझू, सुशीला पिलानियां, नरेण पोटलिया, मनजीत हड़ौली, अमित ढाबी कलां, बिल्लू ढाबी कलां, राज मेहूवाला, सुनील कम्बोज, विजय मेहूवाला और उमराव सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

उन्होंने कहा कि इनेलो प्रदेश के लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने तथा आगामी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। सुनैना चौटाला ने कहा कि जनसमर्थन से ही प्रदेश में बदलाव की नई शुरुआत होगी।

कैथल में एएनसी टीम पर फायरिंग करने वाला फरार तस्कर संदीप पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल

हरियाणा के कैथल जिले में एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हुए मुख्य आरोपी संदीप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदीप के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, वीरवार शाम गांव फरल के पास एएनसी टीम को सूचना मिली थी कि एक कार में सवार कुछ लोग नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कार से पुलिस वाहन को टक्कर मार दी और मौके से भागने की कोशिश की।

कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों अमित, दीपक, विशाल और गुरदीप को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 48.35 ग्राम हेरोइन बरामद की। हालांकि, गांव मटौर निवासी संदीप खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस ने पूरी रात विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। देर रात करीब 11 बजे पूंडरी-फरल नहर के पास एएनसी टीम का संदीप से आमना-सामना हो गया। पुलिस के अनुसार, संदीप ने टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें संदीप के पैर में गोली लगी और

फायरिंग के बाद फरार तस्कर संदीप दबोचा गया

उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

सभी आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी, पुलिस पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि यह गिरोह किन क्षेत्रों में सक्रिय था, इनके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा बरामद हेरोइन की आपूर्ति कहां से की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सभी आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

पालम अग्निकांड में स्काई लिफ्ट फेल होने का दावा

एजेंसी ,नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पालम इलाके में हुए अग्निकांड को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि फायर विभाग की स्काई लिफ्ट खराब होने के कारण बचाव कार्य प्रभावित हुआ। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर स्काई लिफ्ट सही तरीके से काम करती तो अग्निकांड में जान गंवाने वाले नौ लोगों में से कई लोगों को बचाया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और अधिकारियों ने दमकल विभाग की कमियों को छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठा रही थी। भारद्वाज ने यह भी सवाल उठाया कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने में करीब छह महीने का समय क्यों लगा। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।

महिला विवाद में आप विधायक पर भाजपा ने साधा निशाना

एजेंसी ,नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट विधायक वीरेंद्र कादयान और उनके पुत्र अंकित कादयान पर महिला फूल विक्रेता के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने आरोप लगाया कि विधायक के स्टाफ ने महिला के फूलों के स्टॉल से गुलदस्ता लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि पैसे मांगने पर महिला का स्टॉल हटवा दिया गया।
त्यागी के अनुसार, शिकायत लेकर विधायक आवास पहुंची महिला के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि महिला के साथ उसका दो वर्षीय बच्चा भी मौजूद था। भाजपा नेता ने पुलिस पर भी कई दिनों तक मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। नितिन त्यागी ने बताया कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के डीसीपी से मिलकर विधायक और उनके पुत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेतृत्व से भी इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं आरोपों पर विधायक पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

संस्कार भारती ने सिने टॉकीज 2026 का किया शुभारंभ

एजेंसी ,नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा, संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित राष्ट्रीय संवाद मंच 'सिने टॉकीज 2026' का आधिकारिक शुभारंभ संस्कार भारती, कोकण प्रांत की मासिक गोष्ठी में किया गया। मुंबई के डीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल, मालाड में आयोजित कार्यक्रम में आयोजन का पोस्टर चंद्रशेखर वामन वझे, प्रशांत निळकंठ देशपांडे, ऋषिकेश जोशी और ध्रुव कंडपाल ने जारी किया। 'सिने टॉकीज 2026' का आयोजन 11, 12 और 13 दिसंबर को मुंबई के व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, फिल्म सिटी कॉम्प्लेक्स, गोरेगांव में होगा। इस वर्ष की थीम सिनेमा : कल, आज और कल रखी गई है। तीन दिवसीय कार्यक्रम में फिल्मकार, लेखक, शिक्षाविद, तकनीकी विशेषज्ञ और युवा रचनाकार भारतीय सिनेमा के भविष्य, चुनौतियों और बदलते स्वरूप पर चर्चा करेंगे।

बवाना हत्याकांड के दो शार्प शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार

एजेंसी ,नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बवाना के चर्चित जोगिंदर उर्फ काला हत्याकांड में शामिल हिमांशु उर्फ भाऊ और विक्की उर्फ हडल गैंग के दो शार्प शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपितों ने फायरिंग की, जिसमें एएसआई प्रवीण दहिया की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी और उनकी जान बच गई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बवाना निवासी हर्ष वासने और सुल्तानपुर डबास निवासी विपिन उर्फ श्याम सुंदर के रूप में हुई है। दोनों 18 जुलाई को पूठ खुर्द में हुई जोगिंदर की हत्या के मामले में वांछित थे। पुलिस के अनुसार, दोनों रोहिणी में एक और हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। आरोपितों के पास से दो पिस्टल, कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपितों ने गैंग के निर्देश पर हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।

अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को हुई उम्रकैद

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं छह आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।

एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि दोषियों में सुधार की संभावना को देखते हुए उम्रकैद की सजा उचित है।

अदालत ने इससे पहले 13 जुलाई को इस मामले में नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था। इसके अलावा ताहिर हुसैन को भी मामले में दोषी ठहराया गया। वहीं हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, मीर खान, फिरोज, गुल्फाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मुसा को अदालत ने बरी कर दिया।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 जून 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस की जांच में आरोप लगाया गया था कि 24 और 25 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन ने भीड़ का नेतृत्व किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। आरोप पत्र में कहा गया था कि अंकित शर्मा की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी और उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया गया था।

पुलिस के अनुसार, अंकित शर्मा की हत्या खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर हुई थी। हत्या के बाद शव को पास के नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि कुछ लोगों को शव को नाले में डालते हुए देखा गया था। अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई वार के निशान मिले थे।

रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर 51 चोटों के निशान पाए गए थे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन ने चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाने और हिंसा फैलाने में भूमिका निभाई।

ताहिर हुसैन के खिलाफ अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नरवर किले से 500 साल पुरानी अष्टधातु तोप चोरी, धरोहर सुरक्षा पर उठे सवाल

एजेंसी, नई दिल्ली

देश में एक ओर केंद्र सरकार विदेशों में चोरी या अवैध रूप से पहुंचाए गए भारतीय पुरावशेषों और प्राचीन मूर्तियों को वापस लाने के प्रयासों में सफलता हासिल कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर संरक्षित स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों से बहुमूल्य धरोहरों की चोरी के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कला बाजार में भारतीय पुरावशेषों की बढ़ती मांग के कारण तस्कर लगातार प्राचीन मूर्तियों और ऐतिहासिक वस्तुओं को निशाना बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्करी गिरोह के सरगना सुभाष कपूर की वर्ष 2011 में गिरफ्तारी के बाद कुछ समय तक ऐसे मामलों में कमी आई थी, लेकिन अब दोबारा प्राचीन धरोहरों की चोरी की घटनाएं सामने आने लगी हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय की ओर से धरोहरों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर संरक्षित स्मारकों और पुरावशेषों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

ताजा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले स्थित ऐतिहासिक नरवर किले का है। यहां से करीब 500 वर्ष पुरानी अष्टधातु से बनी ऐतिहासिक तोप चोरी हो गई है। इस तोप का वजन तीन हजार किलोग्राम से अधिक बताया जा रहा है। यह धरोहर राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में थी।

विद्या वाहिनी योजना के तहत छात्राओं को मिली साइकिलें, शिक्षा को मिला बढ़ावा

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 3,000 से अधिक छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने, स्कूल तक उनकी सुरक्षित और आसान पहुंच सुनिश्चित करने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस योजना का लाभ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की 1.40 लाख से अधिक छात्राओं तक चरणबद्ध तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छात्राएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें और अपने परिवार, दिल्ली और देश का नाम रोशन करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई छात्राओं को स्कूल आने-जाने में दूरी और परिवहन की समस्या का सामना करना पड़ता है। साइकिल मिलने से उन्हें स्कूल पहुंचने में सुविधा होगी और उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधाएं कम होंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने में भी सहायक साबित होगी।

कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, विधायक रवींद्र नेगी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सरकार का कहना है कि 'विद्या वाहिनी योजना' के माध्यम से छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

चिड़ियाघर में लापरवाही से चिंकारा हिरण की दर्दनाक मौत का आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली चिड़ियाघर में मरम्मत कार्य के दौरान कथित लापरवाही के कारण एक नर चिंकारा हिरण की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाड़े के पास रखी सीमेंट की प्लास्टिक बोरी चिंकारा के सींग में फंस गई थी। इसके बाद घबराया हुआ हिरण काफी देर तक बाड़े में इधर-उधर दौड़ता रहा।

सूत्रों के अनुसार बोरी फंसने के कारण चिंकारा को दिखाई नहीं दे रहा था और वह परेशान होकर भागता रहा। इस दौरान उसका सींग टूट गया और उसे गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि घटना के समय मौके पर कोई कीपर मौजूद नहीं था और सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी।

घायल चिंकारा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इलाज के दौरान पता चला कि उसका एक पैर भी टूट गया था। कुछ दिनों तक उपचार के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई।

चिड़ियाघर कर्मचारियों के मुताबिक यह चिंकारा करीब पांच वर्ष पहले हरियाणा से लाया गया था। आरोप लगाया जा रहा है कि घायल होने के बाद उसे समय पर पर्याप्त इलाज नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई।

इस घटना के बाद चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था और बाड़ों के आसपास चल रहे निर्माण व मरम्मत कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है।

वहीं चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने इस मामले में कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि शाकाहारी जानवरों को बाड़े में दौड़ने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान कभी-कभी चोट लग सकती है। उन्होंने बताया कि घायल जानवरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज दिया जाता है।

अधिकारी के अनुसार वर्तमान में चिड़ियाघर अस्पताल में छोटे-बड़े कुल 18 जानवर उपचार, पुनर्वास और कृत्रिम पालन-पोषण की प्रक्रिया में हैं।

सोनीपत में बम धमकी से हड़कंप न्यायालय और स्कूल निशाने पर

एजेंसी, नई दिल्ली

हरियाणा के सोनीपत जिले में जिला न्यायालय, उपायुक्त कार्यालय और कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। धमकी भरा ई-मेल शुक्रवार सुबह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सोनीपत की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजा गया। ई-मेल सुबह 11 बजकर 6 मिनट पर प्राप्त हुआ।

जानकारी के अनुसार ई-मेल भेजने वाले का नाम बैरी बेकर दर्शाया गया है। संदेश में जिले के कई सरकारी संस्थानों और स्कूलों को अलग-अलग समय पर बम विस्फोट कर निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली स्थित संसद भवन को भी निशाना बनाने की बात लिखी गई है।

ई-मेल में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा कई भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई हैं। संदेश में पांच अगस्त और 15 अगस्त को विस्फोट जैसी धमकियां देने का भी उल्लेख किया गया है। ई-मेल भेजने वाले ने मीडिया संस्थानों को इसकी जानकारी देने और संदेश को आगे प्रसारित करने की बात भी लिखी है।

धमकी भरा संदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। जिला न्यायालय परिसर, लघु सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल की सत्यता, उसके स्रोत और भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई हैं। साइबर विशेषज्ञों की मदद से ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

महिलाओं के लिए पिंक सहेली कार्ड 16 अगस्त से अनिवार्य

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होनी थी, लेकिन अब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने इसे 16 अगस्त से अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। डीटीसी के अनुसार, जिन महिलाओं ने अभी तक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें राहत देते हुए कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। अब 16 अगस्त तक महिलाएं अपना स्मार्ट कार्ड बनवा सकती हैं और उसके बाद डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए यही कार्ड अनिवार्य होगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ना और उन्हें बिना किसी असुविधा के मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।

हरियाणा और आंध्र प्रदेश में एसआईआर से 78 लाख मतदाताओं के नाम हटे

एजेंसी, नई दिल्ली

हरियाणा और आंध्र प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, 15 जून से 24 जुलाई तक चले मतदाता सत्यापन अभियान में हरियाणा में 33.83 लाख और आंध्र प्रदेश में 44.89 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।

चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में कुल 1.727 करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जो कुल मतदाताओं का 83.61 प्रतिशत है। वहीं 33.83 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें 24.13 लाख मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या अन्य कारणों से सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा 7.66 लाख मतदाताओं के निधन की जानकारी मिली, जबकि 2.04 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।

आंध्र प्रदेश में एसआईआर के दौरान 3.71 करोड़ मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए, जो कुल मतदाताओं का 89.22 प्रतिशत है। यहां 44.89 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें 15.22 लाख मतदाताओं की मृत्यु की पुष्टि हुई, जबकि 22.30 लाख मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या अन्य श्रेणी में पाए गए। वहीं 7.37 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिले।

निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा नहीं हुए हैं, उनके नाम स्वतः अंतिम रूप से हटाए नहीं गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में कई कारण हो सकते हैं। इनमें मतदाता का दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाना, तय समय सीमा में प्रपत्र जमा नहीं करना, दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं होना या किसी अन्य कारण से पंजीकरण जारी नहीं रखना शामिल है।

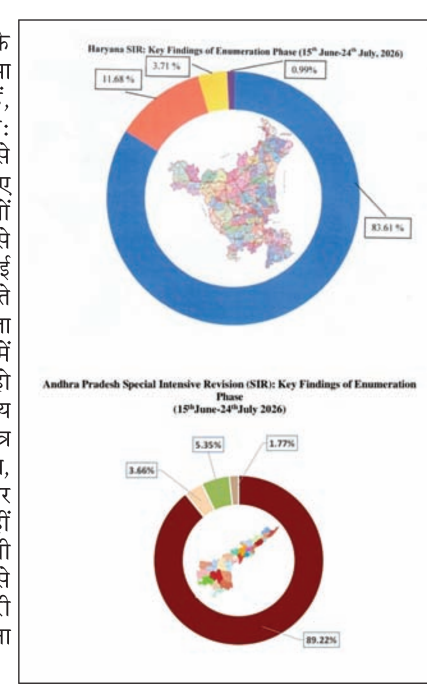

डीयू छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का मिलेगा अवसर

डीयू ने सेमेस्टर अवे प्रोग्राम को दी मंजूरी, छात्रों को मिलेगा वैश्विक शिक्षा अनुभव

एजेंसी, नई दिल्ली

विदेशी विश्वविद्यालयों में एक सेमेस्टर पढ़ाई का मिलेगा अवसर

दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है। अब डीयू के छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में एक सेमेस्टर तक पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से सेमेस्टर अवे प्रोग्राम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय कुलगुरु प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी परिषद की 1283वीं बैठक में लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक अनुभव उपलब्ध कराना है। इसके तहत छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर एक सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकेंगे और वहां की शिक्षा प्रणाली, शोध पद्धतियों तथा नई तकनीकों से परिचित हो सकेंगे।

कुलगुरु प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाना है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विद्यार्थियों को वैश्विक अवसर उपलब्ध कराना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को पांच विषयों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। इसके तहत एमए हिंदी में 200 सीटें, एमए इतिहास में 150 सीटें, एमए राजनीति विज्ञान में 500 सीटें, एमए संस्कृत में 75 सीटें और एमकॉम में 575 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले ही अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

कार्यकारी परिषद ने शिक्षकों के वेतन सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। इस व्यवस्था का लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा, जिन्हें नियमित नियुक्ति से पहले निर्धारित नियमों और अखिल भारतीय चयन प्रक्रिया के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। संबंधित कॉलेज प्रत्येक मामले की जांच करेंगे और विश्वविद्यालय की सहमति के बाद वेतन सुरक्षा लागू की जाएगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2022 से हुई नियुक्तियों पर लागू होगी।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्वविद्यालय, छात्रावासों, प्रोविडेंट फंड और राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े वार्षिक खातों को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कर्मचारियों और अनुबंध कर्मियों के आश्रितों के लिए 20 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज वाली स्वैच्छिक समूह बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।

इस योजना के लिए प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 500 रुपये और जीएसटी प्रीमियम के रूप में देना होगा। बैठक में कुलसचिव डॉ. विकास गुप्ता ने पिछली कार्यकारी परिषद बैठक की कार्यवाही और उस पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अकादमिक परिषद से पारित कई शैक्षणिक प्रस्तावों को भी कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी। वहीं अनुबंध पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कुलगुरु ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों को हटाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनकपुरी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी थाना क्षेत्र स्थित डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में शुक्रवार सुबह आग लगने से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

दमकल विभाग के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह 11 बजकर 23 मिनट पर मिली थी। इसके बाद घटनास्थल पर तीन वाटर बाउजर, एक वाटर टेंडर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक मिनी फायर रेस्क्यू वाहन भेजे गए। शुरुआती अभियान का नेतृत्व एडीओ फिरोज और एसटीओ अमित ने किया। आग की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त संसाधन भी मौके पर भेजे गए। सुबह 11 बजकर 40 मिनट और 11 बजकर 41 मिनट पर एक और वाटर टेंडर रवाना किया गया, जिसकी जिम्मेदारी एसटीओ सरवन लाल को दी गई।

दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित एक कमरे में लगी थी। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोपहर करीब 12 बजे तक आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि आग लगने से कार्यालय में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दमकल विभाग और संबंधित अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं।

इंस्टाग्राम दोस्ती बनी खूनी वारदात, युवक की हुई हत्या

एजेंसी, नई दिल्ली।
सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती एक दर्दनाक वारदात में बदल गई। भारत नगर थाना क्षेत्र के खिम्मन सिंह पार्क में महिला मित्र से मिलने पहुंचे युवक सुनील की पांच नाबालिगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, सुनील और देवकी की दोस्ती करीब तीन महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों पहली बार मिलने के लिए पार्क पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे पांच नाबालिगों ने देवकी पर अश्लील टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। सुनील ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल सुनील की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपित नाबालिगों की भूमिका की जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में उपराज्यपाल ने शैक्षणिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ

छात्रों के लिए बहु-विषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली और तकनीकी कौशल कार्यक्रमों की होगी शुरुआत

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों को बहु-विषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ना है।

समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में केवल एक विषय तक सीमित ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आज की दुनिया को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अलग-अलग क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़कर नई सोच और समाधान विकसित कर सकें। उन्होंने कहा कि ज्ञान की सीमाएं लगातार बढ़ रही हैं और जटिल समस्याओं का समाधान बहु-विषयक दृष्टिकोण से ही संभव है।

उन्होंने विश्वविद्यालय की अपनी डिग्री डिजाइन करें पहल को छात्र-केंद्रित शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रुचि, प्रतिभा और भविष्य की आकांक्षाओं के अनुसार विषयों का चयन कर अपनी शैक्षणिक यात्रा को स्वयं तैयार कर सकेंगे।

कौशल विकास पहल छात्रों को अत्याधुनिक विशेषज्ञता से लैस करेगी

इस अवसर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों में एकीकृत कार्यक्रमों की शुरुआत भी की गई। उपराज्यपाल ने कहा कि विज्ञान आपस में जुड़े क्षेत्रों के सहयोग से आगे बढ़ता है। ऐसे पाठ्यक्रम छात्रों को शोध और नवाचार के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेंगे।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती को समझने के लिए केवल पर्यावरण विज्ञान ही नहीं बल्कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों का भी योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अंतर-विषयक शिक्षा छात्रों को केवल विषय विशेषज्ञ नहीं बनाएगी बल्कि उन्हें व्यापक सोच रखने वाले शोधकर्ता और नवाचारकर्ता के रूप में विकसित करेगी।

समारोह के दौरान क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में वैदिक अध्ययन विभाग की स्थापना और सनातन धर्म तथा भारतीय ज्ञान प्रणालियों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा में आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का ज्ञान भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में पाणिनी का व्याकरण, आर्यभट का खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और भाषा विज्ञान जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें विज्ञान, तर्क, दर्शन और अनुसंधान की समृद्ध विरासत मौजूद है।

उपराज्यपाल ने कहा कि नए कार्यक्रम छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारत की सभ्यतागत ज्ञान परंपरा से जोड़ने का कार्य करेंगे। इससे युवा अपनी जड़ों को समझते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से शुरू किए गए सेमीकंडक्टर कौशल विकास कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया।

उपराज्यपाल ने शिक्षा में नवाचार पर दिया जोर

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी केवल डिग्री प्रदान करना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, अनुसंधान क्षमता और समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की नई पहलें छात्रों को बदलती वैश्विक जरूरतों के अनुसार तैयार करने में मदद करेंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों को इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

सुरक्षा बलों का घने जंगलों में तलाशी अभियान जारी

राजौरी जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर किया सामान बरामद

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। थानामंडी क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने की।

अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों की टीम गुरुवार शाम भंगाई वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही थी। यह इलाका घने जंगलों, ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है। आतंकियों द्वारा अक्सर इन दुर्गम इलाकों का इस्तेमाल छिपने के लिए किया जाता है। तलाशी के दौरान जवानों को जमीन पर कुछ संदिग्ध निशान दिखाई दिए। इसके बाद आसपास के क्षेत्र की जांच की गई

◆ **घने जंगल और पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर आतंकी यहां छिपने की करते हैं कोशिश**

तो लकड़ी और प्लास्टिक की मदद से छिपाया गया एक अस्थायी ठिकाना मिला।

ठिकाने की तलाशी लेने पर वहां से रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बरामद हुआ। इसमें चावल के पैकेट, इंस्टेंट नूडल्स, चाकू, लाइटर, प्लास्टिक शीट, कंबल, गैस स्टोव का नोजल, मोमबत्तियां, पानी की बोतल और खाना बनाने के बर्तन शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान से संकेत मिलता है कि कुछ आतंकी यहां कुछ समय तक रुके हुए थे और जंगल में लंबे समय तक रहने की तैयारी में थे।

न्यूज ब्रीफ

जम्मू पुलिस ने चीनी मांझे पर कसा शिकंजा दुकानदार पर केस

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी प्लास्टिक मांझे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दुकानदार पर मामला दर्ज किया है। डोमाना पुलिस स्टेशन की टीम ने पुरखू कैंप स्थित एक दुकान पर छापा मारकर पांच रोल चीनी मांझा बरामद कर जब्त किया। पुलिस ने दुकानदार राजीव सिंह सलाथिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि यह लोगों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाता है। पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे के कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

डल झील संरक्षण को लेकर पर्यावरणविद ने जताई चिंता

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पर्यावरणविद और निगीन झील संरक्षण संगठन के अध्यक्ष मंजूर वांग्नू ने कहा है कि निशात-सठू सड़क के इस्तेमाल का वह विरोध नहीं करते, लेकिन वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और सड़क किनारे पार्किंग से डल झील की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन झील के संवेदनशील क्षेत्र का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने भारी वाहनों और अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण की मांग की। वांग्नू ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर ही डल झील को सुरक्षित रखा जा सकता है।

रामबन में भूस्खलन, बिसलेरी नाले का प्रवाह प्रभावित

भारतेंदु संवाददाता, रामबन। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के रामसू इलाके में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित बिसलेरी नाले का प्रवाह आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। रामसू के एसडीएम मुजाहिर हुसैन शाह ने बताया कि भूस्खलन उसी क्षेत्र में हुआ है, जहां पिछले वर्ष बड़ा भूस्खलन आया था। हालांकि इस बार स्थिति गंभीर नहीं है और तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

गांदरबल में सड़क हादसा, तीन लोग घायल

भारतेंदु संवाददाता, गांदरबल। कंगन इलाके में शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में तीन लोग घायल हो गए। कारगिल से श्रीनगर जा रही जाइलो कैब हयान पुल के पास बिजली के खंभे से टकरा गई। घायलों को कंगन उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोकरनाग में राइफल चलने से पुलिसकर्मी घायल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसओजी जवान मोहम्मद अल्ताफ की सर्विस राइफल गलती से चल गई, जिससे वह घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी। उन्हें कोकरनाग अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अनंतनाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।

कैट का फैसला, जीएमसी फैकल्टी को वेतन राहत

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की जम्मू पीठ ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू में एकेडमिक अरेंजमेंट पर कार्यरत फैकल्टी सदस्यों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि गर्मी और सर्दी की संस्थागत छुट्टियों के दौरान इन डॉक्टरों का वेतन नहीं रोका जा सकता। कैट के इस फैसले से जीएमसी जम्मू में कार्यरत कई फैकल्टी सदस्यों को राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि छुट्टियां संस्थान की व्यवस्था का हिस्सा हैं और इस अवधि में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगाना उचित नहीं है। फैसले के बाद मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में इसे कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा अहम निर्णय माना जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में 73 ब्लैक कॉरिडोर चिन्हित, हादसों का बढ़ा खतरा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों के लिहाज से 73 खतरनाक ब्लैक कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं। वहीं लद्दाख में एक ब्लैक कॉरिडोर की पहचान की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

◆ **देशभर में 6,358 ब्लैक कॉरिडोर में जम्मू-कश्मीर की हिस्सेदारी 1.15 प्रतिशत**

◆ **सड़क सुरक्षा सुधार के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे**

केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 तक के सड़क दुर्घटना आंकड़ों के आधार पर इन ब्लैक कॉरिडोर की पहचान की गई है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक और ई-डार पोर्टल के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया।

देशभर में कुल 6,358 ब्लैक कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के 73 क्षेत्र शामिल हैं। यह संख्या देश के कुल ब्लैक कॉरिडोर का करीब 1.15 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में 11, पंजाब में 31 और उत्तराखंड में 49 ब्लैक कॉरिडोर दर्ज किए गए हैं। देश में सबसे अधिक ब्लैक कॉरिडोर तमिलनाडु में पाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, ब्लैक कॉरिडोर उन सड़क हिस्सों को कहा जाता है जहां लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की मौत या गंभीर चोट के मामले सामने आते हैं।

भागथली उद्योगों में स्थानीय रोजगार पर उपमुख्यमंत्री का जोर

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को कठुआ के औद्योगिक क्षेत्र भागथली का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों और औद्योगिक इकाइयों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन ने भी जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता का भरोसा दिया है। सुरेंद्र चौधरी ने इरकॉन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह कार्य एक वर्ष पहले पूरा होना था, लेकिन इसमें अनावश्यक विलंब हुआ है।

विस्थापितों ने पीओजेके मुक्ति और अधिकारों की उठाई मांग

पीओजेके विस्थापितों का जम्मू में प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ उठी आवाज

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू । पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से विस्थापित लोगों ने शुक्रवार को जम्मू में प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कब्जे वाले क्षेत्र के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार से पीओजेके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में कदम उठाने की मांग की।

यह प्रदर्शन पीओजेके विस्थापित लोगों के हितों के लिए काम करने वाले संगठन एसओएस इंटरनेशनल की ओर से आयोजित किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के चेयरमैन राजीव चुनी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाए तथा पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग वाले पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए।

राजीव चुनी ने कहा कि पाकिस्तान ने पीओजेके के लोगों का लंबे समय से शोषण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन स्थानीय लोगों को उसका उचित लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, पर्यटन और खनिज संपदा जैसे संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जबकि आम नागरिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कब्जे वाले क्षेत्र के लोगों को अब यह महसूस होने लगा है कि पाकिस्तान उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता।

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का आपसी सहमति से तलाक मंजूर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला ने अपने वैवाहिक संबंध को आपसी सहमति से समाप्त करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की ओर से दायर संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए आपसी सहमति से तलाक की डिक्री को मंजूरी दे दी है।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवाद का समाधान कर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तलाक की डिक्री जारी करने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए दोनों पक्षों

◆ **सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की दी डिक्री**

के बीच हुए समझौते को स्वीकार कर लिया। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति

आलोक अराधे शामिल थे।

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का विवाह वर्ष 1994 में हुआ था। दोनों पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे थे। लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद के बाद दोनों ने सहमति से अलग होने का निर्णय लिया।

कश्मीर में विलो खेती पुनर्जीवन से क्रिकेट उद्योग को सहारा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जल शक्ति, वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय कार्य मंत्री जावेद अहमद राणा ने कश्मीर में विलो की खेती को फिर से बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों को मिलकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य क्रिकेट बैट उद्योग के लिए गुणवत्तापूर्ण विलो लकड़ी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि कश्मीर देश में क्रिकेट बैट निर्माण के लिए विशेष विलो लकड़ी का प्रमुख स्रोत है। इस उद्योग से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। उन्होंने विलो लकड़ी की घटती उपलब्धता पर चिंता जताते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई, पुनरोपण की कमी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण विलो क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। जावेद अहमद राणा ने वन विभाग को घाटी के निचले और दलदली क्षेत्रों की पहचान कर बड़े स्तर पर विलो पौधरोपण करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर युवाओं की मौत का आंकड़ा अधिक

जम्मू-कश्मीर में गिरा सड़क हादसों का ग्राफ, 5 साल में आधी हुईं दुर्घटनाएं, फिर भी 206 जिंदगियां खत्म

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 2026 में अब तक 1,109 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन हादसों में 206 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,658 लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में सड़क हादसों में 18 वर्ष से कम उम्र के 17 लोगों की मौत हुई

मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2,378 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इसके बाद वर्ष 2023 में यह संख्या घटकर 2,342, वर्ष 2024 में 2,120 और वर्ष 2025 में 1,867 रह गई। वर्ष 2026 में अब तक 1,109 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि हादसों में मौत के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला

◆ **जम्मू-कश्मीर में 2026 में 1,109 सड़क दुर्घटनाएं हुईं**

है। वर्ष 2022 में 259 लोगों की जान गई थी, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 294 हो गई। वर्ष 2024 में 271 और वर्ष 2025 में 431 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2026 में मृतकों की संख्या घटकर 206 दर्ज की गई है। मंत्रालय ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वर्ष 2026 के आंकड़े ई-डार पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर हैं, जो अभी अद्यतन हो सकते हैं।

फर्जी दस्तावेजों से 7.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी

ट्रैक्टर ऋण धोखाधड़ी में दो आरोपितों पर आरोप पत्र दाखिल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा जम्मू से ट्रैक्टर ऋण के नाम पर 7.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दो आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ऋण स्वीकृत करवाया और बाद में ऋण राशि का गलत इस्तेमाल किया।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार यह मामला वर्ष 2024 में भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुशील कुमार की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में के-के मोटर्स के मालिक कुलबीर सिंह, अब्दुल हमीद और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी।

जांच के दौरान सामने आया कि अब्दुल हमीद ने भारतीय स्टेट बैंक की तत्काल ट्रैक्टर ऋण योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया था।

मीडिया नीति — हर सरकारी विभाग में नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त, सूचना सत्यापन होगा मजबूत

जम्मू-कश्मीर में फर्जी खबरों पर शिकंजा, नई मीडिया नीति तैयार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट मीडिया नीति-2026 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा परिसर में आयोजित बैठक में सूचना और खनन विभागों से जुड़े आश्वासनों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अली मोहम्मद सागर ने की।

नई मीडिया नीति में फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान स्पष्ट है

बैठक में सूचना विभाग की ओर से समिति को बताया गया कि प्रस्तावित नई मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना और जनता तक प्रमाणित एवं विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना है। नीति के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। ये अधिकारी विभागीय सूचनाओं का सत्यापन करेंगे और सही जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

समिति ने सदन में दिए गए उन आश्वासनों की भी समीक्षा की, जो फर्जी खबरों पर रोक लगाने, भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने और सूचना व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े थे। सूचना विभाग ने बताया कि तथ्य आधारित संचार प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा सूचनाओं की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

समिति के अध्यक्ष अली मोहम्मद सागर ने डिजिटल युग में जिम्मेदार सूचना प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों से निपटने के लिए सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल, आधुनिक संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग और व्यापक जन-जागरूकता अभियान जरूरी हैं। उन्होंने सूचना विभाग को ड्राफ्ट मीडिया नीति-2026 और मीडिया मान्यता प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

बैठक में समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि नई मीडिया नीति में फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए। सदस्यों ने स्वयंभू पत्रकारों पर नियंत्रण, डिजिटल और सोशल मीडिया के नियमन, पत्रकारों की पहचान तय करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में खनन विभाग से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। समिति ने खनन गतिविधियों के नियमन, निगरानी व्यवस्था और विधानसभा में दिए गए विभिन्न आश्वासनों के पालन की स्थिति की जानकारी ली।

जम्मू-कश्मीर के 1371 स्कूलों में एक ही शिक्षक, 32 हजार बच्चों के भविष्य का सवाल, कौन देगा जवाब?

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सरकारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी चुनौती सामने आई है। केंद्र सरकार के यू-डाइस प्लस आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 1,371 सरकारी स्कूल अभी भी केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में करीब 32,303 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही है।

आंकड़ों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 146 ऐसे स्कूल भी हैं, जहां विद्यार्थियों का नामांकन शून्य है। वहीं एकल शिक्षक वाले स्कूलों में एक ही शिक्षक को अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाने के साथ स्कूल के प्रशासनिक कार्य, रिकॉर्ड संभालना, मिड-डे-मील की निगरानी और अन्य जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एक शिक्षक के लिए सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्याप्त समय देना मुश्किल होता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों पर पड़ता है, जहां पढ़ने-लिखने और गणित जैसी बुनियादी क्षमताओं का विकास प्रभावित हो सकता है।

दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्कूलों में मल्टीग्रेड शिक्षण व्यवस्था लागू है, जिसमें अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इससे शिक्षकों के लिए सभी विद्यार्थियों पर समान ध्यान देना चुनौती बन जाता है।

न्यूज ब्रीफ

सीएम सुक्खू ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस व मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर किया नमन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महान क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी शहीद सरदार उधम सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेकर देश के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले शहीद उधम सिंह का अद्वितीय साहस, मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना सदैव राष्ट्रवासियों को देशभक्ति, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन राष्ट्र के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए समर्पित था तथा उनका बलिदान देश के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से समाज के साधारण जीवन को असाधारण अभिव्यक्ति दी। उन्होंने गांव, गरीब और आमजन के जीवन, उनकी भावनाओं तथा संघर्षों को जिस संवेदनशीलता और आत्मीयता से शब्दों में पिरोया, वह आज भी पाठकों के मन को गहराई से स्पर्श करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक चेतना, मानवीय मूल्यों और यथार्थ का सशक्त दस्तावेज है, जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

राम सुभग सिंह का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी व मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वीरवार को जारी आदेशों के अनुसार उनका सेवाविस्तार 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। इस फैसले के साथ प्रदेश में सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। राम सुभग सिंह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें अगस्त 2021 में तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया था। 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। अब सरकार ने उनके कार्यकाल में दो साल की और बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का मानना है कि राम सुभग सिंह ने प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने, प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत फैसलों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के बाद हिमाचल का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने और विशेष वित्तीय सहायता दिलाने के प्रयासों में भी उनकी अहम भागीदारी रही है। इसके अलावा किशाऊ बांध समझौते, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े लंबित मामलों और प्रदेश की पारिस्थितिकी सेवाओं के वैज्ञानिक आकलन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी उनकी भूमिका बताई जाती है। हालांकि, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में सेवा विस्तार की नीति को लेकर लगातार बहस चल रही है। कर्मचारी संगठनों और विपक्ष की ओर से समय-समय पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिए जा रहे एक्सटेंशन पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में राम सुभग सिंह के कार्यकाल में दो साल की बढ़ोतरी ने इस बहस को फिर हवा दे दी है।

एसपी अमित शर्मा राज्यपाल के एडीसी नियुक्त

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए एचपीपीएस (2012 बैच) अधिकारी अमित शर्मा-2 को नई जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) मुख्यालय, शिमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के पद पर तैनात अमित शर्मा-2 को अब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश का एडीसी नियुक्त किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार अमित शर्मा-2 का तबादला तत्काल प्रभाव से किया गया है। अमित शर्मा-2 राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। नई नियुक्ति के बाद वे राज्यपाल के एडीसी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

कार से 5.291 किलो अफीम बरामद, एक काबू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 5.291 किलोग्राम पोस्त (अफीम पोस्त) बरामद किया है। मामले में पुलिस ने कुमारसैन क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान कुमारसैन के महोली गांव निवासी पिंकू राम (42) पुत्र रती राम के रूप में हुई है। वह कार का मालिक है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह मामला थाना कुमारसैन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई डिटेक्शन सेल, उपमंडल रामपुर में तैनात मुख्य आरक्षी (हेड कांस्टेबल) पीयूष राज की शिकायत के आधार पर की। मामले के अनुसार 30 जुलाई की शाम करीब पांच बजे मुख्य आरक्षी पीयूष राज अपनी डिटेक्शन टीम के साथ सैंज और सैंज-लुहरी रोड (एनएच-305) पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सड़क के नीचे की ओर एक कार खड़ी दिखाई दी। पुलिस टीम ने कार के पास जाकर जांच की तो उसमें एक व्यक्ति बैठा मिला। पुलिस ने कार की तलाशी ली। जांच के दौरान कार की डिक्की से 5.291 किलोग्राम पोस्त (अफीम पोस्त) बरामद हुआ। बरामदगी के बाद पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कुमारसैन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

दिव्यांशी का साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बरमाणा में चयन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा की छात्रा दिव्यांशी ने खेलों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के वाटर स्पोर्ट्स एक्सटेंशन सेंटर, बरमाणा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नियमित प्रशिक्षार्थी के रूप में स्थान बनाया है। संग्रीथिन निवासी जसपाल शर्मा की पुत्री दिव्यांशी का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर की ओर से जारी प्रवेश पत्र के अनुसार दिव्यांशी को अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ 6 अगस्त या उससे पहले साई ट्रेनिंग सेंटर बिलासपुर में सहायक निदेशक एवं केंद्र प्रभारी के समक्ष रिपोर्ट करना होगा। दिव्यांशी की इस उपलब्धि पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा की प्रधानाचार्य, शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। स्थानीय लोगों ने भी छात्रा और उसके परिवार को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वह आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगी।

रोहित वत्स धामी ने संभाली कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की कमान, डिजिटल विस्तार पर जोर

संगठन और जनता के बीच डिजिटल संवाद बढ़ाएगी सरकार : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के नवनियुक्त चेयरमैन रोहित वत्स धामी ने दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।

रोहित वत्स धामी ने बताया कि बैठक में कांग्रेस सोशल मीडिया संगठन को आधुनिक, प्रभावी और जनसंपर्क आधारित स्वरूप देने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों के जरिए कांग्रेस की विचारधारा और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में संगठन और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया नेटवर्क को बूथ स्तर तक मजबूत करना, युवा कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संगठन की सक्रियता को बढ़ावा देना प्राथमिकता रहेगी। रोहित वत्स धामी ने मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष संगठन की मजबूती, नवाचार, कार्यकर्ताओं के बेहतर समन्वय और सरकार की विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने को लेकर अपने सुझाव भी रखे।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और पार्टी की नीतियों एवं उपलब्धियों को सकारात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया की बदलती भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन को तथ्यात्मक, सकारात्मक और जनहितकारी संवाद के माध्यम से और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने सोशल मीडिया विभाग को प्रभावी तरीके से काम करने का मार्गदर्शन दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया विभाग पार्टी की आवाज को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में सोशल मीडिया नेटवर्क को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाया जाएगा। बैठक में प्रदेश के समसामयिक राजनीतिक मुद्दों, संगठनात्मक गतिविधियों, जनसंपर्क अभियानों और आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर रोहित वत्स धामी ने पार्टी नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने और संगठन को नई दिशा देने का संकल्प जताया।

आनी में चट्टानें गिरने से चलती कार खाई में गिरी, डॉक्टर व पत्नी की मौत, बेटी घायल

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जिला कुल्लू के आनी उपमंडल में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में श्रीखंड अस्पताल के एक डॉक्टर और उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनकी 18 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

हादसा राणाबाग-देहुरी मार्ग पर करशाइगाड़ के समीप पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर और मलबा गिरने के कारण हुआ। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे कार (एचपी 92ए-4300) राणाबाग-देहुरी सड़क से गुजर रही थी। इसी दौरान पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर और मलबा वाहन पर आ गिरा, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में एक ही परिवार के तीन सदस्य सवार थे। हादसे में श्रीखंड अस्पताल के डॉक्टर बृज लाल (60) और उनकी पत्नी सुनीता (54) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी भव्या (18) गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को तत्काल आनी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत करशाइगाड़ के प्रधान ने प्रशासन और डीपीसीआर कुल्लू को जानकारी दी।

इसके बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया गया। एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र के राणाबाग-देहुरी मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में श्रीखंड अस्पताल के डॉक्टर बृज लाल और उनकी धर्मपत्नी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने तथा घायल पुत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उपमुख्यमंत्री मुकेश ने ली विकास कार्यों की जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार सुबह हमीरपुर से चंबा के लिए रवाना हो गए।

वह वीरवार देर रात को शिमला से हमीरपुर पहुंचे थे और यहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। शुक्रवार सुबह करीब पौने दस बजे चंबा रवाना होने से पहले उपमुख्यमंत्री ने जिला के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से जिला में जारी विभिन्न विकास कार्यों एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लिया। इस अवसर पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, उपायुक्त गंधर्वा राठौड़, एसपी बलवीर सिंह, अन्य अधिकारी तथा कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

नूरपुर में 10.28 ग्राम चिट्टा सहित आरोपी गिरफ्तार, सीआईए टीम ने की कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सीआईए नूरपुर की टीम द्वारा गश्त के दौरान एक युवक को 10.28 ग्राम चिट्टा सहित गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नूरपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की है। वीरवार बीती देर रात को सीआईए नूरपुर की टीम गश्त के दौरान कंडवाल क्षेत्र में मौजूद थी। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर नागनी माता मंदिर बस स्टॉप (कंडवाल) के पास एक संदिग्ध युवक को रोककर उसकी नियमानुसार जांच व तलाशी ली गई । नियमानुसार ली गई तलाशी के दौरान उक्त युवक के कब्जे से 10.28 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान साहिल (उम्र 26 वर्ष), निवासी गांव व डाकघर डागला, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।

एसपी नूरपुर ने पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस संदर्भ में थाना नूरपुर में मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगामी जांच अमल में लाई जा रही है।

धौलाधार वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में पहली बार कैमरे में कैद हुआ हिम तेंदुआ

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है।

धौलाधार वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में पहली बार दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय हिम तेंदुए (स्नो लेपर्ड – पैंथेरा यूनसिया), जिसे 'घोस्ट आफ माउंटेनस' भी कहा जाता है, कैमरे में कैद हुआ है। यह दुर्लभ तस्वीर 21 दिसंबर 2025 को समुद्र तल से 2,836 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुई। यह धौलाधार वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी की जैव विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उप वन संरक्षक रेजिनाल्ड रॉयस्टन ने बताया कि यह उपलब्धि अभयारण्य में अब तक किए गए सबसे व्यापक वन्यजीव कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण का परिणाम है। वर्ष 2023 से 2026 के बीच कुल 117 कैमरा ट्रैप लगाए गए, जिनके माध्यम से 4,238 कैमरा-ट्रैप दिवस का सर्वेक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 के शीतकाल

के दौरान पर्वतीय धारों, दर्रों तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन मार्गों पर वैज्ञानिक अध्ययन एवं स्थानीय पारिस्थितिक जानकारी के आधार पर अतिरिक्त कैमरे स्थापित किए गए। रेजिनाल्ड रॉयस्टन ने कहा कि हिम तेंदुए की उपस्थिति की पुष्टि के साथ धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षण महत्व और बढ़ गया है। अब यह पश्चिमी हिमालय के उन चुनिंदा संरक्षित क्षेत्रों में शामिल हो गया है जहां चार शीर्ष शिकारी प्रजातियां, हिम तेंदुआ, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई काला भालू तथा सामान्य तेंदुआ, एक ही परिदृश्य में पाई जाती हैं। यह तथ्य अभयारण्य की पारिस्थितिक समृद्धि एवं वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से इसकी महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि शोधकर्ताओं के अनुसार कैमरे में दर्ज हिम तेंदुआ संभवत: अपने प्राकृतिक विस्तार क्षेत्र से भ्रमण अथवा विस्थापन के दौरान यहां पहुंचा है।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य कुगती, टुंडाह और नरगू वन्यजीव अभयारण्यों तथा लाहौल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारे के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि यह खोज धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि हिम तेंदुए का यह फोटोग्राफिक रिकॉर्ड धौलाधार पर्वतमाला की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का सशक्त प्रमाण है और हिमालयी वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि साबित होगा।

विधायक सुरेश कुमार ने सम्मू ताल और निर्माणाधीन बस स्टैंड का किया निरीक्षण

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। विधायक सुरेश कुमार ने शुक्रवार को यहां ऐतिहासिक सम्मू ताल के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण और निर्माणाधीन बस स्टैंड के कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति तथा निर्धारित मानकों को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान विधायक ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सुरेश कुमार ने सम्मू ताल में स्थापित की जाने वाली हाई मॉस्ट लाइट का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में भोरंज विधानसभा क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। वर्षों से उपेक्षित रहे इस क्षेत्र में अब करोड़ों रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिससे क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद सम्मू ताल न केवल एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा, बल्कि एक आकर्षक पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट के रूप में भी उभरेगा। यहां स्थापित की जा रही भगवान शिव की 20 फीट ऊंची प्रतिमा क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाइयां देगी और श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी।

विधायक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सम्मू ताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ और सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी।

अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती के बयान की शांता ने की आलोचना

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती द्वारा अनुच्छेद 370 को पुन: लागू कराने के लिए आंदोलन शुरू करने की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बयान से उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ है। शांता कुमार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अनुच्छेद 370 भारत के माथे पर एक बड़ा कलंक था, जिसे हटाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ और उनके त्याग को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि भारत के माथे से मिटा यह कलंक अब दुनिया की कोई भी शक्ति दोबारा नहीं लगा सकती। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चाहे जितना प्रयास कर लें, अनुच्छेद 370 दोबारा लागू नहीं हो सकता।

ऑर्केस्ट्रा ग्रुप विवाद की हो निष्पक्ष जांच, महिला कांस्टेबलों की शिकायत पर कार्रवाई करे सरकार : रणधीर शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा ने प्रथम बटालियन जूंगा के 'हार्मोनी ऑफ द पाइंस' ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़े विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि इस मामले में कर्मचारियों और महिला कांस्टेबलों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायत के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रणधीर शर्मा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के इंस्पेक्टर विजय कुमार को आरोपों की निष्पक्ष जांच पूरी होने से पहले ही निलंबित कर दिया। उनके अनुसार किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई से पहले तथ्यों की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब इसी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में कार्यरत दो महिला कांस्टेबल भी कथित रूप से प्रताड़ना का सामना कर रही हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि हाल ही में स्थानीय गायक की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में दोनों महिला कांस्टेबलों के खिलाफ अभद्र व अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

इसके बाद दोनों ने महिला पुलिस थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। भाजपा नेता ने दावा किया कि महिला कांस्टेबलों की शिकायत में स्थानीय गायक के साथ एक पुलिस अधिकारी का भी नाम शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत के अनुसार दोनों महिला कर्मचारियों पर लगातार दबाव बनाया गया, जिससे वे मानसिक तनाव में आ गईं। रणधीर शर्मा ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एक महिला कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, फिर भी सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पीसीपीएनडीटी कानून के पालन को लेकर विभाग ने दिए सख्त निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर की टीम ने घुमारवीं क्षेत्र में गर्भ में शिशु के लिंग की अवैध जांच पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निजी स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों, क्लीनिकों और एक नशा मुक्ति केंद्र की बिना पूर्व सूचना जांच की गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने मरीजों के पंजीकरण रजिस्टर, अल्ट्रासाउंड मशीनों से संबंधित रिकॉर्ड, अनुमति पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की। साथ ही संस्थान संचालकों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ऐसे निरीक्षण नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं और समय-समय पर बिना पूर्व सूचना के किए जाते हैं। विभाग का उद्देश्य निजी स्वास्थ्य संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का पालन सुनिश्चित करना है।

फीस वृद्धि व छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एबीवीपी का संघर्ष तेज

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने हिमाचल प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों, बढ़ी हुई फीस व छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।

मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में परिषद के पदाधिकारियों ने सरकार पर शिक्षा को अधिकार के बजाय कमाई का माध्यम बनाने का आरोप लगाया। विभाग संयोजक मंजुल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को शिक्षा के केंद्र के बजाय आर्थिक शोषण का माध्यम बना दिया है। उनका आरोप था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों और परीक्षा शुल्क में 25 से 30 प्रतिशत तथा डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में 50 से 60 प्रतिशत तक फीस बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दौर में विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना अनुचित है। जिला संयोजक करण ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा करने वाली सरकार अब छात्रों पर वित्तीय बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक अव्यवस्था का भार विद्यार्थियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। एबीवीपी ने मांग की कि बढ़ी हुई फीस तत्काल वापस ली जाए और छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं।

परिषद ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। आंदोलन के तहत 31 जुलाई को इकाई स्तर पर ज्ञापन, 3 अगस्त को उपायुक्त व एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन, 5 अगस्त को धरना-प्रदर्शन, 6-7 अगस्त को हस्ताक्षर अभियान, 11 अगस्त को रैली व विरोध प्रदर्शन, 13-14 अगस्त को सांकेतिक भूख हड़ताल तथा 17 अगस्त को जिला केंद्रों पर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

राहत बारिश-भूस्खलन के चलते बंद थीं; कांगड़ा घाटी रेलमार्ग संचालन के लिए फिट घोषित

पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक पर 10 दिन बाद दौड़ी ट्रेन

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों की लाइफलाइन कही जाने वाली ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी नैरोगेज रेल सेवा के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले करीब 10 दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बाधित ट्रेनों की आवाजाही अब दोबारा शुरू हो गई है।

रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने ट्रैक का गहन निरीक्षण, सुरक्षा परीक्षण और जरूरी मरम्मत कार्य पूरा करने के बाद इसे ट्रेन संचालन के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया है। इसके बाद शुक्रवार सुबह 5 बजे पहली ट्रेन पठानकोट से जोगिंद्रनगर के लिए रवाना की गई। अब रेल सेवा की निरंतरता मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी। मौसम सामान्य रहने पर पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बीते दिनों हुई भारी बारिश, भूस्खलन और ट्रैक पर मलबा आने के कारण 21 जुलाई को रेलवे प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया था। इसके बाद इंजीनियरिंग टीमें ट्रैक की मरम्मत और मलबा हटाने के काम में जुटी रहीं। पिछले 10 दिनों से कांगड़ा घाटी रेल सेवा बंद रहने के कारण आम लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रोजाना दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज के छात्रों, स्थानीय दुकानदारों और पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। ट्रेनें बंद होने के चलते यात्रियों को मजबूरी में निजी वाहनों या बसों का सहारा लेना पड़ रहा था। बस का किराया रेल किराए की तुलना में करीब पांच गुना अधिक होने से आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। वहीं, सड़कों पर बढ़े ट्रैफिक के कारण सफर में समय भी ज्यादा लग रहा था।

सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यदि मौसम अनुकूल रहा और सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो शुरुआती चरण में सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में सुबह 5 बजे और 7 बजे रवाना होने वाली दो जोड़ी नैरोगेज ट्रेनों को चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के संचालन और ट्रैक की स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी। यदि हालात पूरी तरह सामान्य रहे और दोबारा भूस्खलन जैसी कोई समस्या नहीं आई, तो अन्य ट्रेनों को भी चरणबद्ध तरीके से बहाल कर दिया जाएगा।

पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

रेल ट्रैक के फिट घोषित होने और ट्रेनों की संभावित बहाली की खबर से कांगड़ा घाटी के स्थानीय निवासियों, कारोबारियों और पर्यटकों में उत्साह है। फिरोजपुर रेल डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंजीनियरिंग विंग के निरीक्षण के बाद ट्रैक को सुरक्षित घोषित किया गया है। यदि मौसम अनुकूल रहा और दोबारा भूस्खलन जैसी स्थिति नहीं बनी, तो रेल सेवाएं सुचारु रूप से जारी रहेंगी। रेलवे पूरे रूट पर निगरानी रख रहा है।

यूथ कांग्रेस की विवादित रील पर सियासी संग्राम

आतंकी हवारा के गाने पर बिट्टू बोले- 'गांधी परिवार दे जवाब'; कांग्रेस ने माना- 'गलती से लगा ट्रैक'

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। इंडियन यूथ कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर अपलोड की गई एक रील को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमा गई है।

रील में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे आतंकी जगतार सिंह हवारा के नाम वाले गाने का इस्तेमाल किया गया था। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप पर तीखा हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने वीडियो का हवाला देते हुए बताया कि यूथ कांग्रेस के लाखों फॉलोअर्स वाले ऑफिशियल पेज पर राहुल गांधी के साथ एक विवादित रील अपलोड की गई, जिसके बैकग्राउंड म्यूजिक में आतंकी जगतार सिंह हवारा को ग्लोरीफाई (महिमामंडित) करने वाले बोल चल रहे थे। बिट्टू ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस युवाओं को बम और गोलियों की भाषा सिखाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जसकरण सिंह काहलों ने इसे सोशल मीडिया टीम की 'अनजाने में हुई गलती' स्वीकार करते हुए रील को हटा दिया है।

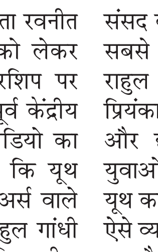

रवनीत सिंह बिट्टू ने इस वीडियो को मीडिया के सामने जारी किया और गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया। बिट्टू ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अब जवाब दें। नीट और छात्र प्रदर्शन के नाम पर युवाओं को भड़काया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के आधिकारिक पेज से ऐसे व्यक्ति को ग्लोरीफाई किया जा रहा है जो देश को तोड़ने वाली ताकतों से जुड़ा है। क्या कांग्रेस युवाओं को बम-गोली और आतंकवाद के रास्ते पर धकेलना चाहती है?

खूबसूरत अंदाज में शेयनिस पलासियोस

निकारागुआ। शेयनिस पलासियोस, निकारागुआ की प्रसिद्ध मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता हैं। उन्होंने वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। वह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक अभियानों से भी जुड़ी रही हैं।

भारोत्तोलन में लवप्रीत सिंह ने रजत डिस्कस थ्रो में सीमा ने जीता कांस्य

सुपर हेवीवेट में 388 किग्रा उठाया भार, स्नैच में राष्ट्रमंडल खेलों का बनाया नया रिकॉर्ड

एजेंसी, ग्लास्गो

भारत के स्टार भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के +110 किग्रा सुपर हेवीवेट वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया, तो वहीं लवप्रीत सिंह ने रजत और डिस्कस थ्रो में सीमा ने कांस्य पदक जीता है। स्कॉटिश इवेंट कैंपस में खेले रोमांचक मुकाबले में लवप्रीत ने कुल 388 किलोग्राम (स्नैच 176 किग्रा + क्लीन एंड जर्क 212 किग्रा) वजन उठाया। स्वर्ण पदक न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी ने कुल 389 किलोग्राम वजन उठाकर केवल एक किलोग्राम के अंतर से जीता।

28 वर्षीय लवप्रीत, जिन्होंने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 109 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता था, इस बार सुपर हेवीवेट वर्ग में और भी दमदार अंदाज में नजर आए। उन्होंने स्नैच में अपने तीनों प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किए। पहले 168 किलोग्राम, फिर 173 किलोग्राम और अंत में 176 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। मुकाबले का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार समोआ के सनेले माओ स्नैच में 175 किलोग्राम के तीनों प्रयासों में असफल रहे और प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसका पूरा फायदा लवप्रीत ने उठाया और 176 किलोग्राम का सफल प्रयास कर स्नैच के बाद 10 किलोग्राम की बढ़त बना ली।

हालांकि, क्लीन एंड जर्क में मुकाबला पूरी तरह बदल गया। लवप्रीत ने 212 किलोग्राम का सफल प्रयास किया, लेकिन 217 किलोग्राम उठाने में असफल रहे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने 223 किलोग्राम का शानदार भार उठाकर क्लीन एंड जर्क का नया खेल रिकॉर्ड बनाया और कुल 389 किलोग्राम के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्होंने तीसरा प्रयास नहीं किया।

हालांकि, स्वर्ण पदक लवप्रीत से एक किलोग्राम दूर रह गया, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उन्होंने बर्मिंघम 2022 के कांस्य पदक से आगे बढ़ते हुए इस बार रजत पदक जीतकर भारतीय भारोत्तोलन अभियान का शानदार समापन किया और अंत तक स्वर्ण के लिए कड़ा संघर्ष किया। भारत की सीमा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 58.65 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। सीमा अपने फाइनल प्रयास में सुधार नहीं कर सकीं और फाउल कर बैठीं, लेकिन तीसरे राउंड में किया गया उनका थ्रो पोडियम पर जगह बनाने के लिए काफी साबित हुआ। शुरुआत फाउल के साथ करने के बाद, उन्होंने 57.32 मीटर और 58.65 मीटर के थ्रो किए, जो आखिरकार कांस्य पदक दिलाने के लिए काफी रहे।

जर्सी विवाद : अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड को बताए बिना लिया फैसला, टिर्की ने मांगा जवाब

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ बोले-मेरी मंजूरी बिना बदला रंग, महासचिव का दावा-सभी पदाधिकारियों को थी जानकारी

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से केसरिया किए जाने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने इस मामले में महासंघ के पदाधिकारियों और महानिदेशक से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि कार्यकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखे बिना और उनकी पूर्व जानकारी के बिना इतना महत्वपूर्ण फैसला कैसे लिया गया।

15 अगस्त से नीदरलैंड और बेल्जियम में शुरू होने वाले हॉकी विश्व कप से पहले जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा, परगट सिंह, वी. भास्करन और धनराज पिल्लै समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। टिर्की ने कार्यकारी बोर्ड को भेजे ईमेल में कहा कि टीम की पहचान और प्रतिनिधित्व से जुड़े फैसले पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चुने गए नेतृत्व और बोर्ड की मंजूरी से ही होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें केसरिया रंग से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि ओडिशा सरकार ने उनसे इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने दावा किया कि जर्सी के रंग में बदलाव की जानकारी सभी पदाधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला खिलाड़ियों और कोचों की मांग पर लिया गया और इस पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अब इस मुद्दे पर कार्यकारी बोर्ड में चर्चा कर आगे का फैसला लिया जाएगा।

स्पोर्ट्स विंडो

बनारस की कराटे खिलाड़ी गौरी पाठक वर्ल्ड पुलिस गेम्स में चयनित

एजेंसी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी लहरतारा निवासी कराटे खिलाड़ी गौरी पाठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए भी चयनित हुई है। हाल में ही गौरी ने 11वें ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर-2026 में व्यक्तिगत कुमिते (-61 किग्रा) स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। गौरी के इस स्वर्णिम सफलता पर जिला कराटे संघ ने खुशी जताई है। शुक्रवार को जिला कराटे संघ के महासचिव दिलीप कुमार सैनी व कोच किसलय मानव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित 9वें साउथ एशियन कराटे प्रतियोगिता में गौरी पाठक ने रजत पदक जीता था। यह प्रतियोगिता 5 से 6 जुलाई तक खेली गई। बनारस की गौरी पाठक ने भारतीय टीम में जिले का प्रतिनिधित्व किया। गौरी पाठक वर्तमान में सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान में गौरी मानव अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से सेकेंड डिग्री ब्लैक बेल्ट है। पदाधिकारियों के अनुसार गौरी ने महज 8 वर्ष की आयु में कराटे सीखना शुरू किया और वाराणसी स्थित मानव अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स से प्रशिक्षण प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतने तथा एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, वर्ष 2019 में उनका चयन सीआरपीएफ में स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से हुआ।

इटली के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी बारेसी का निधन

एजेंसी, मिलान। इटली को 1982 फीफा विश्व कप जिताने वाली टीम के सदस्य और एसी मिलान के महान डिफेंडर फ्रांको बारेसी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी शुक्रवार को एसी मिलान ने दी। हालांकि क्लब ने मृत्यु के कारण का खुलासा नहीं किया। एसी मिलान ने शोक संदेश में कहा कि आज केवल क्लब का परिवार ही नहीं, बल्कि उसका गौरवशाली इतिहास भी शोक में डूबा है। क्लब ने कहा कि फ्रांको बारेसी उसकी आत्मा और पहचान थे तथा उनकी ईमानदारी, समर्पण और खेल भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अगस्त 2025 में बारेसी के फेफड़े में गांठ (पल्मोनरी नोड्यूल) निकालने के लिए सर्जरी हुई थी। इसके बाद उनका इम्यूनोथेरेपी से इलाज चल रहा था। उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति इस वर्ष फरवरी में मिलान-कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में रही थी, जहां उन्होंने पूर्व फुटबॉलर ज्यूसेपे बर्गोमी के साथ सैन सिरो स्टेडियम में ओलंपिक मशाल लेकर प्रवेश किया था। फ्रांको बारेसी ने अपना पूरा 20 वर्षीय पेशेवर करियर केवल एसी मिलान के साथ बिताया। 17 वर्ष की उम्र में क्लब से जुड़ने वाले बारेसी ने 700 से अधिक मैच खेले और 1980 तथा 1990 के दशक में एसी मिलान को विश्व फुटबॉल की सबसे सफल टीमों में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। 1997 में संन्यास के बाद एसी मिलान ने उनके सम्मान में छह नंबर की जर्सी को स्थायी रूप से रिटायर कर दिया था।

डेकाथलनः तेजस्विन शंकर ऊंची कूद के बाद दूसरे स्थान पर

एजेंसी, ग्लास्गो। तेजस्विन शंकर ने ऊंची कूद में 2.15 मीटर की कूद लगाकर 944 अंक हासिल किये और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरूषों की डेकाथलन स्पर्धा में कनाडा के डेमियन वार्नर के बाद दूसरे स्थान पर हैं। पांच प्रतिस्पर्धाओं के बाद वार्नर 4353 अंक लेकर शीर्ष पर हैं, जबकि तेजस्विन के 4339 अंक हैं। इंग्लैंड के सैमी बॉल 4249 अंक लेकर तेजस्विन से 90 अंक पीछे हैं। तेजस्विन ने ऊंची कूद में 944 और लंबी कूद (7.82 मीटर) में 1015 अंक बनाए। उन्होंने सौ मीटर में 10 . 96 सेकंड का समय निकालकर 870 अंक हासिल किए। शॉटपुट में उन्होंने 13 . 09 मीटर का ही थ्रो फेंका और सिर्फ 673 अंक बना सके। फिर 400 मीटर में 49.51 सेकंड का समय निकालकर वह पांचवें स्थान पर रहे और उन्हें 837 अंक मिले।

यूएई ने 2027 महिला अंडर-19 टी-20 विश्वकप में बनाई जगह

एजेंसी, दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर के फाइनल में मलेशिया को एक रन से हराकर 2027 महिला अंडर-19 टी-20 विश्व कप में जगह बना ली है। अगले साल होने वाले टूर्नामेंट के लिए खेले गए इस क्वालीफ़ायर में आठ टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में यूएई की टीम केवल 95 के स्कोर पर ऑल आउट हुई थी, लेकिन उन्होंने इस स्कोर को भी सफलतापूर्वक बचाव किया। बल्ले से 31 रन बनाने के बाद अल मसीरा जहांगीर ने गेंदबाजी में 12 रन देकर दो विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच बनीं।

श्रीलंका ने पाकिस्तान 6 विकेट से हराया

पहले टी-20 में दुलानी ने लगाया शतक, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

एजेंसी, दांबुला

इमेशा दुलानी की शानदार नाबाद शतकीय पारी के दम पर श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मुकाबले में पाकिस्तान को छह विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ श्रीलंका ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 176 रन बनाए। शवाल जुल्फिकार ने सर्वाधिक 61 रन की पारी खेली। कप्तान मुनीबा अली ने 42 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके अलावा इमान नसीर ने 21, आयशा जफर ने 17 और सायरा जबीन ने 13 रन जोड़े।

श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी ने दो विकेट हासिल किए, जबकि काव्या कविंदी, सुगंधिका कुमारी और चामुदी प्रबोदा ने एक-एक विकेट लिया। 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम को इमेशा दुलानी ने संभाला। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 101 रन बनाए और टीम को छह गेंद शेष रहते जीत दिला दी। उनकी पारी में आक्रामकता के साथ बेहतरीन संयम देखने को मिला। इस जीत से श्रीलंका का आत्मविश्वास बढ़ा है, जबकि पाकिस्तान को अगले मुकाबले में वापसी कर सीरीज बराबर करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

ब्राजील की फुटबॉल टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगी मैत्री मैच

एजेंसी, ब्रासीलिया। ब्राजील फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि राष्ट्रीय टीम 2026 फीफा विश्व कप के बाद पहले अंतरराष्ट्रीय अवकाश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैत्री मैच खेलेगी। महासंघ ने बताया कि राष्ट्रीय टीम 25 और 29 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे और फिर तीन अक्तूबर को भारत का सामना करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच टाउन्सविले के क्वींसलैंड कंट्री बैंक स्टेडियम में होगा, जिसके चार दिन बाद वे ब्रिस्बेन में सनकॉर्प स्टेडियम में सॉकरूस के साथ एक और मुकाबले के लिए रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में अपने दो मैच खेलने के बाद, ब्राजील की टीम भारत के कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी, जहां वे तीन अक्टूबर को साल्ट लेक स्टेडियम में पहली बार भारत का सामना करेंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए मसूद

एजेंसी, नई दिल्ली

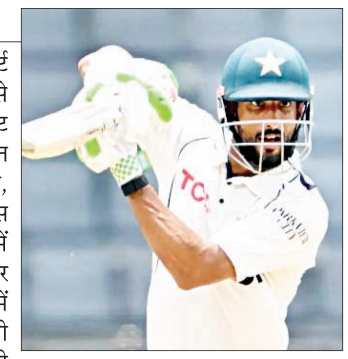

वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में रविवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शान मसूद की कमी खलेगी, क्योंकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को उंगली में चोट के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है। तरौबा में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए जेडेन सील्स की गेंद लगने से मसूद के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी। पाकिस्तान यह मैच 90 रन से हार गया था। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में भी मसूद के खेलने पर संदेह है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा है कि 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में उनकी उपलब्धता उनके ठीक होने पर निर्भर करेगी। पीसीबी ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान के टेस्ट बल्लेबाज शान मसूद को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। स्कैन और क्लिनिकल जांच के बाद, शान का इलाज अभी पाकिस्तान टीम का मेडिकल पैनल कर रहा है।' पीसीबी ने कहा, '19 अगस्त से लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच में उनकी उपलब्धता उनके ठीक होने और क्लिनिकल प्रोग्रेस (सुधार) पर निर्भर करेगी।' साथ ही यह भी बताया गया कि मसूद 'टीम के साथ ही रहेंगे।'

पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी और मसूद के बाहर होने से क्वींस पार्क ओवल में होने वाले दूसरे मैच के लिए टीम के सामने खिलाड़ियों के चयन की चुनौती होगी। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील-जिन्हें अब्दुल्ला फजल के पीठ की चोट के कारण सीरीज से बाहर होने के बाद टीम में शामिल किया गया था - मसूद की जगह लेने के दावेदारों में शामिल हैं। बिना टेस्ट खेले बल्लेबाज अवैस जफर भी टेस्ट डेब्यू की दौड़ में हैं।

पाकिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट, 34 मजदूरों की मौत

एजेंसी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 34 खनिकों की मौत हो गई। हादसा क्वेटा के बाहरी इलाके सोरंगे में विस्फोट के बाद खदान का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कई मजदूर अंदर फंस गए।

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अनुसार, बचाव दल अब भी सुरंग में फंसे अन्य खनिकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तक खदान से छह और शव निकाले गए, जिससे मृतकों की संख्या 34 पहुंच गई।

बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने हादसे की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य की सभी कोयला खदानों में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

खान एवं खनन मंत्री शोएब नोशिरवानी ने बताया कि बचाव अभियान मुश्किल परिस्थितियों में भी जारी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को तीन-तीन लाख रुपये सहायता देने की घोषणा की।

खदान मालिक के अनुसार, हादसा मीथेन गैस विस्फोट के कारण हुआ। घटना के समय खदान में 42 मजदूर काम कर रहे थे। पाकिस्तान के बलोचिस्तान और सिंध प्रांतों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण खदान हादसे अक्सर सामने आते रहते हैं।

पीएम मोदी आज आंध्र और कर्नाटक दौरे पर

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दोनों राज्यों में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। करीब 5,640 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता 60 लाख है। इसमें एआई, बायोमेट्रिक यात्री सुविधा और आधुनिक बैगेज सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राज्य की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना से चिप निर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा वह अक्षय ऊर्जा, विद्युत पारेषण और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनसे ऊर्जा वितरण, सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

हिंदू राष्ट्र और राजशाही के पक्ष में नहीं नेपाल सरकार : पीएम बालेंद्र शाह

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार न तो हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के पक्ष में है और न ही राजशाही की वापसी का समर्थन करती है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बहाली के साथ राजशाही का मुद्दा भी जुड़ जाता है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित नहीं होगा।

मधेश-केंद्रित राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ शुक्रवार को लगभग दो घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि सरकार संघीय व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपने कार्यकाल में इस व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प निभाएगी। बैठक में मौजूद जनता समाजवादी पार्टी के महासचिव रामकुमार शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नहीं हैं। तराई/मधेश में हिंदू राष्ट्र की मांग का अलग संदर्भ है, जबकि पहाड़ में इसका अलग अर्थ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र आने पर राजशाही भी उससे जुड़ जाती है, इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। इससे संघीय व्यवस्था कमजोर होगी।

रामकुमार शर्मा ने बताया कि मधेशवादी नेताओं ने प्रधानमंत्री से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल हिंदू राष्ट्र की अवधारणा उचित नहीं है और सरकार संघीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाएगी।

राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में दोहराया कि वह और उनकी पार्टी संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित पक्ष के साथ हुए सभी समझौतों को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री के हवाले से महतो ने कहा कि कुछ तत्व सांप्रदायिक दंगे भड़का कर अपने स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना होगा।

सेंसेक्स 166 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,383 के स्तर पर पहुंचा

एजेंसी, मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी का रुख देखने को मिला। सेंसेक्स 166 अंक की बढ़त के साथ 78,094 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 66 अंकों की तेजी दर्ज की गई और यह 24,383 अंक पर पहुंच गया। बाजार में ऑटो और मीडिया कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों की सकारात्मक धारणा के चलते प्रमुख सूचकांकों में मजबूती बनी रही।

इससे पहले 30 जुलाई को भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। उस दिन सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 के स्तर पर पहुंचा था, जबकि निफ्टी में 67 अंकों की तेजी रही और यह 24,317 अंक पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों का असर घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है।

सूरत से अहमदाबाद तक ग्रीन कॉरिडोर में पहुंचाया गया हृदय, रेलवे ने रचा इतिहास

देश में पहली बार लाइव हार्ट लेकर दौड़ी वंदे भारत

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए पहली बार जीवित हृदय (लाइव हार्ट) को सुरक्षित पहुंचाकर नया इतिहास रच दिया है। सूरत से अहमदाबाद तक ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस से हृदय को लाया गया। इसका प्रत्यारोपण अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में किया जाएगा।

यह पूरा अभियान समय के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हृदय को निर्धारित समय सीमा के भीतर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और गुजरात पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे बिना किसी रुकावट के हृदय को अस्पताल पहुंचाया जा सका।

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेदप्रकाश ने कहा कि जीवनरक्षक अभियानों में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे, आरपीएफ, गुजरात पुलिस और चिकित्सा टीमों के बेहतर तालमेल से यह मिशन सफल हुआ।

रेलवे के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस की तेज गति, समयपालन और भरोसेमंद सेवा ने इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस उपलब्धि से साबित हुआ है कि भारतीय रेल केवल यात्री और माल परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपात स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

रेलवे ने कहा कि इस मिशन में चिकित्सकों, अंग प्रत्यारोपण समन्वयकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह अभियान मानव जीवन बचाने के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

2011 से अलग रह रहे उमर अब्दुल्ला-पायल का तलाक

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को तलाक की मंजूरी दे दी है। उनकी शादी 32 साल पहले हुई थी। दोनों 2011 से अलग रह रहे थे। दोनों ने कोर्ट को बताया कि आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी विवादों को सुलझाने का फैसला किया है।

उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया था। उमर और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हुई थी। यहां दोनों जॉब करते थे। इन दोनों के दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि दोनों ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शादी को खत्म करने के लिए आवेदन दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष गंभीरता दिखाएंगे और मामला सुलझ जाएगा। सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक नहीं देना चाहतीं और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं।